हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 11:00 बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उठाना चाहता हूं। आज सभी अख़बारों में यह खबर छपी है कि मण्डी जिला में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में अनुसुचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी आप बैठ जाइये। ये जो सुबह का 11.00 बज़े से 12.00 बज़े तक का समय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यह समय प्रश्नकाल का होता है। आप अपनी बात बाद में रख सकते हैं। ...(व्यवधान) नेगी जी आप बैठिए। मैं इस पर अपना व़क्तव्य देना चाहता हूं। आज दिनांक 28.02.2020 को 10.12 बज़े श्री जगत सिंह नेगी, माननीय सदस्य की ओर से नियम-67 के अंतर्गत स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है जोकि मण्डी जिला के शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खाने में भेदभाव व अत्याचार से संबंधित है। जिस पर माननीय सदस्य तुरंत चर्चा करना चाहते हैं। यह सूचना 10.12 बज़े प्राप्त हुई है जबकि यह सदन की कार्यवाही से एक घंटा पहले प्राप्त होनी चाहिए थी। यह प्रस्ताव निश्चित समयावधि पर इस सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने इस विषय पर विचारोपरांत पाया है कि हिमाचल प्रदेश प्रक्रिया एंव कार्य संचालन नियामावली के नियम-67 के तहत उचित नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य इस विषय पर नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं परंतु विषय सामयिक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल संक्षिप्त में आप अपनी बात रख सकते हैं।

28.02.2020/1100/DT/HK-2

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस लोक महत्व के विषय को यहां पर रखने को मौका दिया है। जैसा मैं कह चुका हूं कि मंडी शिवरात्रि मेला अंतर्राष्टीय मेला है और आज जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मंडी जिला में जोकि माननीय मुख्य मंत्री जी का गृह क्षेत्र है और माननीय मंत्री महेन्द्र सिंह जी का भी क्षेत्र है, इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। मंडी का यह अंतर्राष्ट्रीय मेला है और सरकार के नाक के नीचे यह मेला होता है। इसमें सारा पैसा सरकार की ओर से खर्च किया जाता है। वहां पर देवताओं को प्रशासन के द्वारा बुलाया जाता है और इस तरह से बुलाकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह एक बार नहीं हुआ, इससे पहले स्कूल में मीड-डे मील में छात्रों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया गया। उसके बाद हमारे विधायकों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया था। माननीय मंत्री और विधायकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। यह बहुत ही निंदनीय बात है और

श्री एन.जी. द्वारा जारी

28-02-2020/1105/एच.के.-एन.जी./1

श्री जगत सिंह नेगी जारी.....

और यह मेरा सरकार पर आरोप है कि यह सरकार अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों के साथ भेदभाव करने पर तुली हुई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।...(व्यवधान) आपकी मानसिकता बिलकुल गलत है और आपकी मानसिकता में जातिवाद छाया हुआ है। इस मानसिकता के कारण प्रदेश के मन्दिरों में मंत्री और विधायक तक नहीं जा सकता। आपकी सरकार दलित विरोधी सरकार है और हम

इस सरकार का विरोध करते हैं। अध्यक्ष माहोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सरकार को दिशा-निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में शामिल प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोगों के ख़िलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान) इस प्रकार की घटनाएं बार-बार क्यों घट रही हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी आपका सारा विषय आ गया है कृपया आप बैठ जाएं। जो विषय माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने यहां पर रखा है कि 27 फरवरी, 2020 को मण्डी शिवरात्रि मेले में आयोजित सामुहिक भोजन के दौरान घटित घटना बारे, इसके संदर्भ में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी अपनी स्टेटमैंट जारी करेंगे।

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। प्रदेश के महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक मेलों में मण्डी शिवरात्रि एक प्रमुख मेला है। 'मेला' शब्द का अभिप्राय लोगों में आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना है जिसमें जात-पात का कोई स्थान नहीं है।

मण्डी शिवरात्री के दौरान श्रद्धालुओं और आम जनता की सुविधा हेतु भण्डारे का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22 फरवरी, 2020 को भण्डारे का आयोजन किया गया था जहां जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सबको खाना

परोसा गया था। दिनांक 27 फरवरी, 2020 को एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव व डाकखाना पंजाई, तहसील बाली चौकी ने मण्डी शहर की पुलिस चौकी में आकर चौकी प्रभारी को एक शिकायत दर्ज करवाई कि जब 27 फरवरी, 2020 को श्री सुशील कुमार स्वयं तथा श्री इन्द्र सिंह एवं बिट्टू राम के साथ DIET में सामुहिक धाम में खाना खाने गये तो उन्हीं के गांव के श्री विजय कुमार ने उन्हें वहां बैठने

से यह कहकर मना किया कि यह जगह आप लोगों के लिए नहीं है? उन्होंने गाली गलौच भी की। इसके पश्चात थाची वार्ड से जिला परिषद सदस्य श्री दिला राम भी मौका पर आए और उन्हें मारने की धमकी भी दी यदि वह वहां से नहीं हटते हैं।

इस शिकायत के आधार पर FIR संख्या 63/2020 u/s 504 व 506 IPC तथा SC/ST (Prevention of Atrocities Act) की धारा 3(I)(r), 3(I)(U), 3(I)(Za) तथा 3(I)(d) के अंतर्गत थाना पुलिस मण्डी में दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले की तफ्तीश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी को सौंपी गई है। दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।

आज के आधुनिक युग में किसी भी प्रकार का जाति सम्बन्धित भेदभाव आपत्तिजनक एवं निंदनीय है और हमारी सरकार इसकी कड़ी भर्त्सना करती है। सरकार ऐसे विषयों के बारे में अत्याधिक गंभीर है और इस सम्बंध में कड़ाई से कार्रवाई करेगी।

मैं माननीय सदन को कहना चाहता हूं कि मण्डी में शिवरात्रि का मेला अन्तर्राष्ट्रीय मेला है जिसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं। केवल मण्डी जिला से नहीं अपितु पुरे देश से और बाहर के मुल्कों से भी हज़ारों लोग आते हैं। जो कुछ भी हुआ है यह निंदनीय है और हमारी सरकार आपको विश्वास दिलाती है

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2020/1110/JK/YK/1

जल शक्ति मंत्रीः-------**जारी**------

कि इसको किसी भी प्रकार से रोकने और न ठहरने का प्रयास किया जाएगा। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी सारा विषय आ गया है। ...(व्यवधान) सरकार की तरफ से स्टेटमैंट आ गई है। अभी प्रश्नकाल है, प्लीज आप सभी लोग बैठ

जाएं। जगत सिंह नेगी जी प्लीज आप बैठें। माननीय मंत्री जी ने सरकार की तरफ से वक्तव्य दे दिया है।

...(व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे।)

वैसे नियमानुसार तो जो आपने नोटिस दिया था वह कवर ही नहीं होता है। अब सरकार की तरफ से भी वक्तव्य आ गया है। सरकार ने अपनी स्टेटमैंट दे दी है। ...(व्यवधान) प्लीज आप सभी लोग बैठ जाएं।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बर्हिगमन किया।)

वैसे नियमों के तहत जो नोटिस दिया गया था उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था, परन्तु विषय बहुत सामायिक था, इसलिए उसको यहां पर रखा गया। माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से सारी बात रखी है। अब प्रश्न काल आरम्भ होगा।

28.02.2020/1110/JK/YK/2

प्रश्न संख्याः 1303

अध्यक्षः श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 1385

Shri Hoshyar Singh (Dehra): Speaker, Sir, the information given and laid down on the Table of the House says that the last year upto 15th January, 2019, the State Government have provided employment to 8908 persons. जिसमें सिर्फ 1304 लोग are on regular basis and 7604 are on contract basis. Speaker, Sir, I

want to know जो कांट्रेक्ट बेसिज पर है और 7,604 क्या इन्हें रैगुलर करने का सरकार विचार रखती है, यदि रखती है तो इसके क्या मापदण्ड हैं?

जल शक्ति मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, सदस्य महोदय ने जो जानना चाहा है, मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ करके हाऊस को सूचित करना चाहता हूं कि आपने एक स्पैसिफिक पीरियड़ की सूचना मांगी है, उस स्पैसिफिक पीरियड़ में जो भर्ती होनी हैं, उसमें आपने जानना चाहा कांट्रेक्ट भर्तियों के रैगुलराइजेशन के बारे में। हमारे R&P रूल्ज़ बने हुए हैं, उनमें सारा प्रावधान है, जैसे-जैसे उनका पीरियड़ पूरा होगा वैसे-वैसे ही वे रैगुलर किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 8,908 भर्तियों के अलावा हमारी सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के बीच में 4,278 नये पद विभिन्न विभागों के अन्दर सृजित किए हैं, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया आजकल चली हुई है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

28.02.2020/1115/SS-YK/1

प्रश्न संख्याः 1385 क्रमागत

जल शक्ति मंत्री क्रमागत :

इसके अलावा हमारी सरकार ने दो वर्षों के कार्यकाल में 15315 पदों को भरने की स्वीकृति दे दी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू है। इसके अलावा 4 हजार ऐसे पद हैं जिनको पी0एस0यूज0, बिजली बोर्ड और एच0आर0टी0सी0 में भरने की स्वीकृति दी हुई है। उनको भी भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अनेकों ऐसी और भी छोटी-छोटी भर्तियां हैं जैसे जल शक्ति विभाग के अंदर 1578 पद अभी-अभी स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा पहले जो 1372 जल रक्षक थे जिनको अब डेली वेज पर किया हुआ है, वे अलग से भरे गए हैं। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि ज्यादा-से-ज्यादा बेरोज़गार नौजवानों को हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, पी0एस0यूज0, बोर्ड/कारपोरेशन के माध्यम से रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार उस तरफ काम कर रही है।

अध्यक्ष : धन्यवाद।

28.02.2020/1115/SS-YK/2

प्रश्न संख्याः 2345

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल सरकार के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा सुन्दरनगर में कोई स्टेडियम बनाने की योजना है?

वन मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न यह था कि क्या एच0पी0सी0ए0 सुन्दरनगर में कोई क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है? अध्यक्ष महोदय, एच0पी0सी0ए0 एक स्वायत्त संस्था है और वह अपने निर्णय व गतिविधियां स्वयं करती है। इसलिए इसकी कोई जानकारी या सूचना मेरे पास नहीं है।

दूसरा, प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सुन्दरनगर में इसके अतिरिक्त कोई स्टेडियम इत्यादि बनाने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने 10.35 करोड़ रुपये की एक डी0पी0आर0 बना करके भेज दी है जिसमें 70 लाख रुपया भी डाल दिया है और उस स्टेडियम को हम बहुत अच्छे से बनाकर देंगे।

28.02.2020/1115/SS-YK/3

प्रश्न संख्याः 2346

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चिन्तपुरनी मंदिर के परिसर का विस्तारीकरण करने के लिए जिन 32 दुकानों वाली जगह का अधिग्रहण किया जाना, उन लोगों को कब तक पैसे की अदायगी कर दी जायेगी?

दूसरा, जो वहां पर हैलीपैड बनाने की स्वीकृति दी गई है क्या उसके लिए भी मंदिर ट्रस्ट से पैसा उपलब्ध करने का विचार है?

जल शक्ति मन्त्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, हैलीपैड के लिए 1.10 करोड़ रुपये की राशि ऑलरेडी स्वीकृत/जारी कर दी गई है और साथ में जिन दुकानों का आप ज़िक्र कर रहे हैं उनको एक्वायर करने की प्रक्रिया जारी है। **जैसे ही वह प्रक्रिया पूरी होगी तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर इस काम को किया जायेगा।**

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से दे दिया है।

28.02.2020/1115/SS-YK/4

प्रश्न संख्याः 2347

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष जी, जो सूचना सभापटल पर रखी है उसमें डिटेल में उत्तर दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 700 करोड़ रुपये का Integrated Development Project है

जारी श्रीमती के0एस0

28.02.2020/1120/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या 2347 जारी---

श्री पवन कुमार काजल जारी---

और इससे पहले जो मिड हिमालयन वाटरशैड प्रोजैक्ट चला था उसमें भी कांगड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कोई पंचायत नहीं थी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र को इससे पहले भी वंचित किया था और अब जब यह नया प्रोजैक्ट आई.डी.पी. आया है, अभी भी वंचित है। क्या भविष्य में इसमें कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र को शामिल करेंगे?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को यह सूचना देना चाहूंगा कि पिछले कल भी राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए विपक्ष ने जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजैक्ट्स और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रोजैक्ट्स के बारे में कहा? अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आई.डी.पी. वन विभाग का एक प्रोजैक्ट जो कि विश्व बैंक द्वारा फंडिड है और जिसकी प्रारम्भिक मीटिंग्ज़ हुई है, प्री-नेगोसियेशन मीटिंग 19 और 20 दिसम्बर, 2019 को हुई और उसके बाद 2 और 3 जनवरी, 2020 को नेगोसिएशन मीटिंग डी.ई.ए. और वर्ल्ड बैंक के मध्य हुई और अभी 18 फरवरी, 2020 को लोन अप्रूव हो गया है। लोन एग्रिमेंट 15 दिनों के भीतर होने वाला है जिसमें 700 करोड़ रुपया जो प्रदेश को मिलने वाला है। उसमें से 80 प्रतिशत यानि 560 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी और 140 करोड़ यानि 20 प्रतिशत स्टेट का शेयर होगा। माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायतें इसमें क्यों नहीं ली गई हैं, तो डी.ई.ए. के द्वारा कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उनके आधार पर कहीं पर कुछ चीजें फिट नहीं बैठी होंगी उसका यह कारण होगा। वैसे अभी कांगड़ा जिला की लगभग 64 ग्राम पंचायतें इस परियोजना के अंदर ली गई हैं जिसमें से प्रदेश की 428 ग्राम पंचायतें हैं। उसमें एक क्राइटेरिया तो यह भी था कि जो पहले अगर किसी परियोजना में रह चुके हैं उनको नहीं लेना है और फिर दूसरा, उस ब्लॉक में अगर कोई बैकवर्ड एरिया सब प्लान की

28.02.2020/1120/केएस/एजी/2

पंचायत है तो उसमें लेना है। कांगड़ा का क्षेत्र क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था लेकिन मैं आपको डैफिनेटली एक बात कहूंगा कि जो पंचायतें, क्योंकि प्रदेश में 3273 के लगभग पंचायतों में से 428 पंचायतें इसमें आई हैं और पहले का जो प्रोजैक्ट था उसमें 728 पंचायतें थीं, हमारा इसका जो सैकिण्ड फेज़ है, यदि आवश्यक होगा तो उसमें निश्चित रूप से लेंगे।

श्री आशीष बुटेल (पालमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी प्रोजैक्ट के बारे में 26.08.2019 को एक प्रश्न प्रश्न संख्या 1416 किया था और उसमें क्राइटेरिया बताया गया था। 11 प्वाइंट का क्राइटेरिया हमें उस समय दिया था जिसके अंदर मेरे हिसाब से पालमपुर की ऑलमोस्ट सभी पंचायतें आ जाती हैं लेकिन इस बार इस प्रोजैक्ट के अंदर सिर्फ दो पंचायतें ली गई हैं। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोजैक्ट है तो कांगड़ा जिला में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एग्रिकल्चर का विस्तार हुआ है । उसमें से सिर्फ 66 या 65 पंचायतें, जो भी माननीय मंत्री जी ने बताईं, वे बहुत कम हैं । तो क्या इसमें आप और पंचायतों को लेने की कोशिश करेंगें? खासकर पालमपुर विधान सभा क्षेत्र को, जो एडिशनल क्राइटेरिया आपने दिया है, उन मापदंडों के हिसाब से जो हमारी पंचायतें इसके अंदर आती हैं, क्या उन्हें भी इस प्रोजैक्ट का हिस्सा बनाएंगे?

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है और जो मापदंड हैं, उनके आधार पर ही होगा। मापदंडों में कहा गया है कि पूर्व में क्रियान्वित अथवा समानांतर बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र/ग्राम पंचायत आई.डी.पी. परियोजना में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। और सैकिण्ड यह था कि वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र, प्रोटैक्टिड एरिया नैटवर्क से बाहर की गई उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विकासात्मक कार्यों से वंचित रहीं एवं सन्निहित समूहों में संस्पर्शी हैं। प्रदेश के 10 जिलों की इस श्रेणी की 98 ग्राम पंचायतों में से 48 ग्राम पंचायतों को इस मापदण्ड के अनुरूप होने पर परियोजना में सम्मिलित किया गया है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.2.2020/1125/av-ag/1

प्रश्न संख्या : 2347---------- क्रमागत

वन मंत्री----- जारी

इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो 431 चिन्हित पिछड़ी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से 96 को शामिल किया गया है। हमने पूरे जिला के मुताबिक जो पंचायतें ली हैं उसमें जिला सिरमौर की 46, सोलन 42, शिमला 36, बिलासपुर 36, कुल्लू 46, मण्डी 49, ऊना 36, कांगड़ा 64, हमीरपुर 37 और चम्बा की 36 हैं। मैंने कहा कि **जो पंचायतें फेज़-ii में आवश्यक मापदंड के अनुसार आयेंगी उनको हम अवश्य सम्मिलित करेंगे।**

28.2.2020/1125/av-ag/2

प्रश्न सख्या : 2348

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष प्लानिंग की मीटिंग में भी यह मुद्दा माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष उठाया था और उन्होंने उस समय जिलाधीश महोदय को यह आदेश दिए थे कि इस बारे में सारी प्रक्रिया पूरी करके तत्काल भेजा जाए और उन्होंने वहां से सारी औपचारिकताएं पूरी करके यह सारा मामला भेजा भी है। हमारे लिए दिक्कत यह है कि जब हमारा अपना ब्लॉक ऑफिस है तो ये पंचायतें कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक के अधीन है जिस कारण से हमारे कई कार्य नहीं हो पाते हैं। इसको शामिल करने में सरकार को न कोई कठिनाई होगी और न ही इसमें कोई ज्यादा व्यय होगा इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ये पंचायतें मेरे ब्लॉक में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि प्रदेश में ऐसे 80 ब्लॉक्स हैं जिनका विधान सभा क्षेत्रवार सृजन नहीं हुआ है। क्षेत्रीय और भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ये विकास खंड बनाये गये हैं। ऐसी 44 पंचायतें हैं और इनकी कांगड़ा ब्लॉक के अंदर 12 पंचायतें आती हैं जिसका माननीय सदस्य ज़िक्र कर रहे हैं। अभी जनगणना की प्रक्रिया शुरू है जो कि 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक चलेगी इसलिए यह प्रक्रिया पूरी होने तक इस तरह का कोई भी नया काम आरम्भ नहीं किया जा सकता। अगर इन्होंने लिखकर के भेजा है तो निश्चित तौर पर 31 मार्च, 2021 के बाद हम इस के बारे में विचार करेंगे।

28.2.2020/1125/av-ag/3

प्रश्न संख्या : 2349

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को इस मामले की वास्तविक स्थिति से स्वयं भी अवगत करवाया था। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो

टी सी द्वारा जारी

28-02-2020/1130/TCV/AS-1
प्रश्न संख्या : 2349 .....क्रमागत
श्री राम लाल ठाकुर ...जारी

वर्ष 2011 में जो प्रोजैक्ट सैंक्शन हुआ था, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गये और वह मसला लटका रहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक मेले के समापन समारोह में पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल साहब वहां गये थे। उन्होंने अलाउंस किया था कि यह सब्जी मंडी यहां पर खुलेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां पर आपने आधारशिला रखी है, उससे 100 गज की दूरी पर डाइट इन्स्टिच्यूशन है। यह शिक्षा विभाग का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर शिक्षा विभाग के अध्यापकों की ट्रेनिंग होती है। उससे लगभग 80 मीटर की दूरी पर डिग्री कॉलेज, जुखाला है, जहां पर छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जहां पर आपने फांउडेशन स्टोन रखा है उससे 50 मीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि 50-60 मीटर के इस एरिया में जहां इतने शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। अगर आप वहां पर सब्जी मंडी खोलेंगे तो उस एरियाज़ में सबसे ज्यादा टमाटर होते हैं, जब सब्जी वहां पर आती है तो कुछ सब्जी सड़ जाती है। इसलिए क्या आप सब्जी मंडी ऐसी जगह में बनाना चाहते हैं, जहां स्कूल, कॉलेज और

डाइट इन्स्टिच्यूशन को दिक्कत हों? इसके लिए ज़मीन की फाइल बनीं थी और अली खड्ड के किनारे पर जगह चिन्हित की गई थी। वहां पर सब्जी मंडी होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। एक बाबा जी बैठते थे, उनको भी जिलाधीश ने वहां से उठा दिया था और वहां पर कुछ पेड़ थे उनको भी वन विभाग ने काट दिया था। अब सड़क के किनारे सब्जी मंडी को न बना करके डिग्री कॉलेज के प्रांगण में बनाया जा रहा है, यह कौन-सा न्याय हो रहा है? आप सब्जी मंडी दे रहे है या जो छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। इसलिए सरकार इस पर विचार करे और जहां पर इस सब्जी मंडी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, उसको वहां से उठा करके जहां पर जिला प्रशासन ने जगह चिन्हित की है, वहां पर सब्जी मंडी बनें।

28-02-2020/1130/TCV/AS-2

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस साइट को बदला गया था। माननीय सदस्य जहां पर सब्जी मंडी चाहते हैं, वहां पर फॉरेस्ट की वज़ह से साइट डवलपमैंट करना बहुत

ही मुश्किल था। इसलिए वह जगह उचित नहीं थी और उसको बदला गया है। जहां तक वहां पर विभिन्न शिक्षा संस्थानों की बात है तो इसके लिए उन्होंने एन0ओ0सी0 दिए हैं। उनके एन0ओ0सी मिलने के बाद ही ज़मीन विभाग के नाम हुई है और उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसैस शुरू किया अन्यथा हम इसको पहले चिन्हित की गई साइट पर ही बनाना चाहते थे। अब इसकी साइट को बदलना संभव नहीं है क्योंकि हमने इसके टेंडर कर दिए हैं और जुलाई, 2020 तक यह कार्य पूरा किया जाना है। इसके लिए 45 लाख रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया गया है और इसका कार्य शुरू हो चुका है।

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको प्रैस्टिज इश्यू न बनाएं। मैंने आपसे बात की थी तो आपने यह कहा कि पूर्व मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, इसलिए हम उसको पूरा करेंगे। यदि पूर्व मुख्य मंत्री ने घोषणा कर भी दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप यह कह रहे हैं कि हमें

एन0ओ0सी0 मिल गये हैं। माननीय मंत्री जी जिस दिन आप बिलासपुर जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले सरकार का आदेश हुआ कि आप एन0ओ0सी0 दो ....

एन.एस. द्वारा जारी।

28-02-2020/1135/NS/AS/1

प्रश्न संख्या : 2349 .....क्रमागत

श्री राम लाल ठाकुर .....जारी

और इस ज़मीन को कृषि विभाग के नाम पर करो। आपने कहा कि उस जगह पर ज्यादा खर्चा होना था। आप मेरे साथ मौके पर चलें मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि जिलाधीश के माध्यम से उस जगह के लिए वन विभाग के पास फाइल गई हुई है और उस ज़मीन में कोई खर्चा नहीं है यह जगह बिल्कुल प्लेन है। वहां पर आप चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी सब्जी मंडी खोल दो लेकिन ऐसे ही प्रेस्टीज़ इश्यू बनाना न तो लोगों के हित में है और न ही सरकार के हित में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें और मौके पर चलें।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम लाल जी ने ठीक कहा है। ये मुझे मिले थे और मेरी इनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि जहां पर आपने शिलान्यास किया है वहां पर एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन्ज़ हैं। मैंने इनको स्पष्ट कहा कि जब वर्ष 2011 में घोषणा हो चुकी है तो दोबारा इस जगह को बदलने का कोई मतलब नहीं था और इसे राजनीतिक तौर पर बदला गया था। मैंने कहा कि मैं इसको देखूंगा और अगर ठीक होगा तो नहीं बदलेंगे अगर ठीक नहीं हुआ तो मैंने बदलने की बात कही। मैंने दोबारा कागज़ात मंगवाए और कहा कि आप मुझे बताईए कि क्या हमें एन0ओ0सी0 मिला है? हमें डाइट इंस्टीच्यूशन ने एन0ओ0सी0 दे दिया है और उसी के आधार पर ही हमने लैंड ट्रांसफर की है। मैंने इनको कहा था कि अगर एन0ओ0सी0 नहीं लिया होगा तो निश्चित तौर पर सब्जी मंडी वहां नहीं बनेगी। जब डाइट ने एन0ओ0सी0 दिया है तो निश्चित रूप से सब्जी मंडी वहीं बननी है और वहीं बनेगी तथा यह निर्धारित है।

28-02-2020/1135/NS/AS/2

प्रश्न संख्या : 2351

श्री जवाहर ठाकुर (दरंग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र की 60 प्रतिशत पंचायतें पिछड़े क्षेत्र में आती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है कि अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों के 231 पद रिक्त चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाज़िब है। प्रश्न के जवाब में भरे गए पदों व स्वीकृत पदों का ब्यौरा दिया गया है। दरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की सैंक्शंड स्ट्रैंथ 763 हैं और इसमें से केवल 118 पद खाली हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कुछ पद रिटायरमैंट्स से खाली हो जाते हैं और कई बार कुछ अध्यापक किसी कारण से नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं या तबादले हो जाते हैं और फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो इस कारण से खाली रहते हैं। वहां पर 118 पद खाली हैं। यह बात ठीक है कि इनका क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या पूरी होनी चाहिए। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या पूरी हो। हमने दो वर्षों में दिनांक 31.01.2020 तक जो पद भविष्य में भरे जाने हैं उसके लिए कैबिनेट से सैंक्शन ले ली है और ये पद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर व हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को भर्ती के लिए भेज दिए गए हैं। माननीय सदस्य के ही विधान सभा क्षेत्र में कुल 212 पदों पर नई भर्तियां की गई हैं। कुछ प्रमोशन्ज़ से भेजे गए हैं और कुछ ट्रांसफर किए गए हैं, ये अलग से हैं। **मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम बहुत शीघ्र इन सारे पदों को भर देंगे।**

अध्यक्ष : माननीय जवाहर जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए?

श्री जवाहर ठाकुर .....श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

प्रश्न संख्याः2351... जारी

श्री जवाहर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जो अध्यापकों के 500 से ज्यादा रिक्त पद थे उनमें विभाग द्वारा लगभग 212 पद पिछले दो वर्षों में भर दिए गए हैं और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रवक्ताओं के 51 पद रिक्त पड़े हैं और अन्य श्रेणियों के सबसे ज्यादा पद भी मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही रिक्त हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए यहां प्राथमिकता के आधार पर इन रिक्त पदों को भरा जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में काफी चिंतित हैं और इनकी चिंता वाजिब भी है, क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछले पांच वर्षों में स्कूल खोलने की रफ्तार तो बढ़ी परंतु जितने पद भरे जाने चाहिए थे, वे पद नहीं भरे गए। विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में आपके निर्वाचन क्षेत्र में 212 नई नियुक्तियां की गई हैं। यदि मैं वर्तमान और पूर्व सरकार के समय के आंकड़े बताऊं तो दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2017 तक कुल 3,290 नई नियुक्तियां की गई हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 तक 6,238 नियुक्तियां की गई हैं। पूर्व सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में 7,131 नियुक्तियां की गई हैं। यानी पिछले पांच वर्षों में कुल 7,131 नियुक्तियां की गई थी और हमारी सरकार द्वारा दो वर्षों में 6,238 नियुक्तियां की गई हैं। आप नियुक्तियों का तुलनात्मक आंकड़ा देख सकते हैं। माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिक्तियां क्यों रखी गई, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। हमने वर्तमान में आपके निर्वाचन क्षेत्र में 212 पद भरे हैं। विभाग द्वारा अन्य पदों को भरने की प्रकिया जारी है और इसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल ले ली गई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना

चाहूंगा कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर बाकी रिक्तियों को भरा जाएगा।

28.02.2020/1140/RKS/DC-2

<u>प्रश्न संख्याः 2352</u>

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज)ः माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चारों तरफ खड्डों से घिरा हुआ है। एक तरफ सीर खड्ड है जोकि जाहू क्षेत्र से निकलती है। इसी तरह दूसरी चैंथ, तीसरी कुनाह और चौथी सुनैहल खड्ड है। चैक डैम, डाईक और पोंड बनाने हेतु इन खड्डों को विधायक प्राथमिकता में डाला गया था लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सूचना दी गई कि 'कार्य प्रगति पर है'। अगर इन खड्डो में चैक डैम बनते हैं तो इससे अवैध खनन पर भी विराम लगेगा और पानी का स्तर भी बढ़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत इन खड्डों की डी.पी.आर्ज. कब तक बनेगी?

श्री डी.टी. द्वारा... जारी

28.02.2020/1145/DT/DC-1

प्रश्न संख्याः2352 जारी

जल शाक्ति मन्त्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में, जो इनकी विधायक क्षेत्र प्राथिमिकता है, उसमें सभी विभागों की सूचना जाननी चाही है।

जिसमें 2018-2019 में सड़क निर्माण लठवान से लदरौर, इस पर लोक निर्माण विभाग सर्वे इन्वेटिगेशन तरफ बड़ा है और इस स्कीम की डी0पी0आर0 विभाग से अपेक्षित है। इस सड़क के लिए अभी तक प्रधान, ग्राम पंचायत से पत्राचार करने के उपरान्त भी भूमि मालिकों द्वारा लोक निर्माण विभाग, भोरंज को गिफ्ट डीड नहीं दी गई है। मेरा अपनी

छोटी बहन से आग्रह रहेगा कि इस पर अमल करें। जैसे ही भूमि की गिफ्ट डीड हो जायेगी तुरन्त इसकी डी0पी0आर0 बना दी जायेगी।

दूसरा इनका प्रश्न सड़क वाहदेवी बाईपास से हरिजन बस्ती होते हुए बोहन के सम्बन्ध में है । इस स्कीम की डी0पी0आर0विभाग से अपेक्षित है। इसमें सड़क प्रधान, ग्राम पंचायत, बगवाड़ा के माध्यम से भूमि मालिकों से गिफ्ट डीड मांगी गई है जो अभी तक लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि इस पर भी आप काम करें।

तीसरा प्रश्न वर्ष 2019-2020 में निर्माण सड़क जाहू से चंदरूही वाया बडेहर, जोल कोहटा दो पुल सहित , इसमें डी0पी0आर0 विभाग से अपेक्षित है और यहां पर भूमि विवाद है। प्रधान ग्राम पंचायत से पत्राचार किया गया है। यहां भी जब तक भूमि का विवाद सुलझाया नहीं जाता तब तक डी0पी0आर0 बनाना मुश्किल है।

चौथा प्रश्न निर्माण सड़क समलोग से गौटा एक पुल सहित। इसमें भी भूमि विवाद है।

पांचवा प्रश्न लघु सिंचाई योजना है यह जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है। इस स्कीम की डी0पी0आर0 बनाने का कार्य प्रगति पर है। मैं को कहूंगा कि विभाग इसकी डी0पी0आर0 तुरन्त एवं समय रहते बनाये।

28.02.2020/1145/DT/DC-2

छठा प्रश्न वर्ष 2019-2020, भोरंज विधान सभा क्षेत्र की कुनाह खडड का तटीयकरण । इस स्कीम की डी0पी0आर0 706.66 लाख, दिनांक 20-2-2020 को वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को भेज दी गई है। इससे अगला है ग्रामीण पेयजल योजना में भोरंज विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं का सम्वर्धन और सुधार। इस स्कीम को हमनें ADB में लिया हुआ है। एशियन डबलपमैंट बैक की एक ऐसी स्कीम है जो वर्ष 2000 से पहले की बनी हुई है उनकी रेनोवेशन के लिए उसको एक प्रोजैक्ट में डाला गया है जो की ADB Grid HH11 , for Rs. 3206.00 उसमें प्रस्तावित है। ए0डी0बी0 का जो मिशन है वह अब

आ रहा है। पुरानी उठाऊ पेयजल योजनाओं में राईजिंग मेन व पम्पिंग मशीनरी को बदलना। इसमें भी स्टेट सैक्टर में 70 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।

भोरंज विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वोर-वैल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना। इस स्कीम का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। क्योंकि भोरंज विधान सभा चुनाव क्षेत्र, सरकाघाट विधान सभा चुनाव क्षेत्र, धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र व घुमारवीं चुनाव क्षेत्र, इन चारों विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के ग्राउण्ड वाटर में बहुत दिक्कत है। 2019-2020, समलोग डैम से उठाऊ पेयजल योजना। इस स्कीम के कार्य का भी सर्वेक्षण चला हुआ है।

भोरंज विधान सभा की लगवालती बमसन पेयजल योजना का सम्वर्धन और सुधार। इस योजना को हमने जल जीवन मिशन में लिया है। यह आपकी सबसे बड़ी चिन्ता थी। आप इसके बारें मे बार-बार कहती थीं॥ इस योजना का प्रोफार्मा प्राक्कलन 4541.22 रूपये का बना है और जो प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वकृति के लिए प्रस्तावित है।

उठाऊ पेयजल योजना जाहू का सुधार एवं नवीनीकरण। इसको भी हमने ए0डी0बी0 में डाला है। जैसा मैंने पहले भी कहा की इसे 3206.00 की योजना में डाला गया है। आपके विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह सडकों की बात है, चाहे वह जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है, चाहे किसी अन्य विभाग से है, जो आपकी एम0एल0ए0 प्रायोरिटी है उसमें टोप प्रायोररटी में काम किया जायेगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश जी, माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत विस्तार से इसमें उत्तर दे दिया है।

श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री...एन.जी द्वारा जारी

28-02-2020/1150/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2352 जारी.....

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तरफ से अंगुठा दिखाया जा रहा है जिसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूं। हमारी सरकार में ही हमारे चैंथ खड्ड के तटीयकरण हेतु 4.5 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इसके अलावा 'हर घर को जल, हर घर को नल' योजना के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र को 3 करोड़ रुपये मिला है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास के अनेक काम हुए हैं लेकिन अभी कईं काम होने बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28-02-2020/1150/एच.के.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या-2353

श्री पवन नैय्यर (चम्बा): अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें बताया गया है कि 2 स्कूल बिना टीचर के चले रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि यह दोनों स्कूल कैसे चले हुए हैं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चम्बा जिला में पांच विधान सभा क्षेत्र आते हैं और यह दोनों स्कूल किस-किस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं? प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि कुल 142 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिंगल टीचर हैं और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आश्वासन चाहता हूं कि इन 142 स्कूलों में शेष स्टाफ कब तक भरा जाएगा?

शिक्षा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया और जिस प्रकार से उसका उत्तर दिया गया है उससे यह साबित होता है कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है। वास्तविक रूप से जो चीज़ फिल्ड में होती है सरकार द्वारा उसे ही इस माननीय सदन में बताया जाता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष: कृपया बैठे-बैठे न बोलिए।

शिक्षा मंत्री: यह 2 स्कूल जिन्हें बिना टीचर के लिखा गया है इसका मतलब यह है कि उन स्कूलों में स्वीकृत पोस्ट के अगेंस्ट रेगुलर टीचर नियुक्त नहीं किया गया है बल्कि वहां पर

अन्य स्कूलों से टीचरों को प्रतिनियुक्त किया गया है और वे वहां जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए यह कहना कि वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है। इन दोनों स्कूलों का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला सकरीना-2 और राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुवान है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि टीचरों की भर्तियां समय-समय पर होती रहती हैं। स्कूल अपग्रेड हो जाते हैं, कईं स्थानों पर रिटायरमैंट हो जाती है और कईं स्थनों पर प्रमोशन होने के बाद स्थान खाली हो जाता है इसलिए अनेक स्थानों पर वैकेंसी होती रहती है। हिमाचल प्रदेश में दिनांक 01-01-2013 से लेकर दिनांक 31-12-2017 तक प्राथमिक शिक्षा में कुल 7,131 नियुक्तियां

28-02-2020/1150/एच.के.-एन.जी./3

हुई हैं। जबकि वर्तमान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान दिनांक 01-01-2018 से आज तक कुल 6,268 नियुक्तियां की गई हैं। अभी 5,938 पोस्टें खाली हैं जिन्हें भरने के लिए हमने कैबिनेट से स्वीकृति लेकर कमीशन के पास भेज दी हैं और इसके लिए बैच वाईज़ प्रोसेस चल रहा है। इसके अतिरिक्त इस साल 31-12-2020 तक जो पोस्टें खाली होंगी उनको भरने के लिए भी आगे प्रोसेस किया है और कैबिनेट से स्वीकृति लेकर हमीरपुर के सलैक्शन कमीशन को और उप-निदेशकों को बैच वाईज़ भरने के लिए आदेश दे दिए गए हैं

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2020/1155/JK/HK/1

प्रश्न संख्याः 2353ः------जारी------

ताकि भविष्य में यदि वे पोस्टें खाली होती हैं तो उनको भरने का एडवांस में प्रोसैस शुरू हो जाएगा। यहां पर चम्बा जिला की प्रॉब्लम है। चम्बा, सिरमौर और शिमला का कुछ इंटीरियर एरिया, जहां पर टीचर्ज़ भेजना मुश्किल होता है लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम इन्हीं जिलों में भेजते हैं फिर अगर कोई

मोडिफिकेशन के लिए रिक्वैस्ट आती है तब उनको थोड़ा-बहुत कन्सीडर करते हैं अदरवाइज़ प्रायोरिटी के आधार पर चम्बा में टीचर्ज़ की भर्तियां कर रहे हैं और आगे भी यह प्रोसैस जारी रहेगा। सिरमौर और शिमला में भी यह प्रोसैस आगे जारी रहेगा।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ज़वाब दिया, पहली बात तो यह है कि ये जवाब में अपने विषय से ही भटक गए। यह प्रश्न प्राइमरी स्कूल्ज़ का है, जे.बी.टी. का है। आप जो ज़वाब 6000 और 7000 का दे रहे हैं उसमें टी.जी.टी.लैक्चरर भी शामिल हैं। Please stick to the issue as this issue is regarding Chamba district. चम्बा जिले की जो आपने रिक्तियां बताई हैं, सबसे ज्यादा रिक्तियां घरोला ब्लॉक में 26 जे.बी.टी. और सलूणी में 24 हैं। मैक्सिमम रिक्तियां यहां पर हैं। पवन नैय्यर जी ने जो आपसे प्रश्न पूछा दो स्कूल जो बिना टीचर्ज़ के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डिप्यूट करके चल रहे हैं। आप दो स्कूल में प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हैं। जिस स्कूल से आप डिप्यूट कर रहे हैं वहां पर भी टीचर्ज़ नहीं है और जहां पर आप डिप्यूट कर रहे हैं वहां पर भी टीचर्ज़ नहीं हैं। न टीचर वहां जाता है और न दूसरी तरफ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 143 schools are running without teachers or with single teacher. Two schools are running without teachers. आपके बहुत सारे ऐसे स्कूल्ज़ हैं जहां पर 4-4, 5-5 टीचर्ज़ हैं मगर स्टूडैंट्स की संख्या कम है। क्या आप इसको रैशनेलाइज़ करेंगे कि जिन स्कूल्ज में स्टूडैंट्स की संख्या कम है, वहां से टीचर्ज़ को ट्रांसफर करके उन स्कूलों में भेज दिया जाए जहां पर स्टूडैंट्स की संख्या ज्यादा है। दूसरे, जो रिक्तियां एच.टी. और सी.एच.टी. की हैं , these are promotional posts. इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप प्रमोट करें और इन

28.02.2020/1155/JK/HK/2

पोस्टों को भरिए। 14 रिक्तियां एच.टी. की हैं और 9 सी.एच.टी. की हैं। These are promotional posts. इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यह जो 143 स्कूल्ज़ हैं, इनकी आप स्ट्रैंथ मंगवाएं कि इनमें कितनी स्टूडैंट स्ट्रैंथ है और मैं आपको बता

रही हूं कि ऐसे-ऐसे स्कूल्ज़ हैं जहां पर 5-5 टीचर्ज़ बैठे हैं और वर्किंग पोजीशन में हैं। But the students strength is below 60-70. ये वे स्कूल्ज़ हैं जहां पर सिंगल टीचर है। यहां पर students strength is also 50-60. इसको यदि आप रैशनेलाइज़ करेंगे तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसका आपको you will get a better output and better गुणात्मक शिक्षा जो हम चाहते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़े और इसमें आपको फायदा मिलेगा

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो कि शिक्षा मंत्री भी रहीं हैं। इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित रूप से मैं अमल करूंगा। जो जे.बी.टी. के बारे में इन्होंने पूछा है, टोटल चम्बा जिला में 1191 गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल्ज़ हैं, जे.बी.टी. में कुल जो सैंक्शंड स्ट्रैंथ है वह 2313 की है, जिसमें से 2144 पोस्टें भरी हुई हैं और 169 पोस्टें खाली हैं। एच.टी. के 240 पद स्वीकृत हैं, 226 भरे हुए हैं, उनमें सिर्फ 14 पद खाली हैं। सी.एच.टी. की 214 पोस्टें सैंक्शंड हैं, जिनमें से 205 पद भरे हुए हैं, केवल 9 पद खाली हैं। जो रिटायरमैंट वगैरह होती रहती है, उससे पोस्टें खाली हो जाती हैं और प्रमोशन प्रोसैस में थोड़ा समय लगता है। ये सारी पोस्टें कम्पलीट हो जाएंगी। 169 के लिए भी जे.बी.टी. की टैट का ऑलरेडी ही हमीरपुर के सबोर्डिनेट सर्विस सलैक्शन कमिशन को उसकी रिक्विजिशन गई है। उन्होंने एप्लिकेशन्ज़ इन्वाइट भी कर दी हैं लेकिन बीच में कुछ कोर्ट के केसिज़ हैं जिसके कारण भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे ही हमारे कोर्ट केसिज़ समाप्त हो जाते हैं, हम निश्चित रूप से इन सभी रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरेंगे और जो आपने सुझाव दिए हैं

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

28.02.2020/1200/SS-YK/1

प्रश्न संख्या : 2353 क्रमागत

शिक्षा मंत्री क्रमागत :

कि उन पर प्रॅमोशन इत्यादि जल्दी हो जाए, उनको भरा जायेगा। यह ठीक है कि डिप्यूट करने से पद खाली रहते हैं और आपने रेशनलाइजेशन के लिए भी सुझाव दिया है, कई स्थानों पर टीचर ज्यादा होंगे और कहीं पर कम रहते हैं, उनको भी ऑलरेडी रेशनलाइज करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। चम्बा और जहां पर टीचर्ज़ कम हैं वहां उसको हम एक्सपीडाइट करने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न काल समाप्त

28.02.2020/1200/SS-YK/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। माननीय कृषि मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय वन मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमैंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28.02.2020/1200/SS-YK/3

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष : अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। अब मैं माननीय सदस्य, श्री राजेश ठाकुरा जी से कहूंगा कि वे इस चर्चा में हिस्सा लें।

श्री राजेश ठाकुर (गगरेट) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस प्रस्ताव

को श्री बलबीर सिंह जी ने रखा और श्री राकेश जम्वाल जी ने इसका अनुसमर्थन किया। दो दिन से लगातार राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। ये जो तीन घंटे का दस्तावेज आदरणीय गवर्नर साहब ने इस माननीय सदन में पढ़ा, उसमें अनेकों योजनाएं धरती पर उतरीं और उनमें काम हुआ है। परन्तु लगातार हमारे विपक्ष के साथी एकमत से यही कह रहे थे कि कोई भी काम नहीं हुआ। जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ तो अखबार में उनकी एक खबर लगी कि यह आंकड़ों का जाल है, यह एक राजनीतिक दस्तावेज है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार स्वास्थ्य, सड़क, जल-पानी के ऊपर क्या काम करती है? हमारी सरकार ने किसान सामान्य निधि के अंतर्गत 8.46 लाख लोगों को लाभ दिया। गृहिणी योजना के अंतर्गत 2.76 लाख लोगों को सिलेण्डर और गैस कनेक्शन मुफ्त मिले। वहां जल जीवन मिशन में हर घर में नल लगने की योजना बनी। वहां एक ऐसा काम हुआ, जब विधान सभा शुरू हुई थी तो ध्वाला साहब कहते थे कि स्कूलों के हालात इतने नीचे गिर गए हैं कि दो मास्टर और तीन बच्चे स्कूल में हैं। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने स्कूलों में प्री-एजुकेशन शुरू की। यह 3740 स्कूलों में शुरू हो चुकी है और 49 हजार से ज्यादा बच्चे प्री-एजुकेशन में इस बार दाखिला ले चुके हैं। उन बच्चों को खेलने व दूसरे सामान के लिए 60 हजार रुपया प्रति स्कूल दिया गया। इसके लिए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। इन्वैस्टर मीट जैसा सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने धर्मशाला में किया। यह कोई छोटा काम नहीं था, जहां देश के प्रधान मंत्री आकर इंवैस्टर्ज़ के बीच बोलते हैं कि यह मेरा प्रदेश है। यह पहली बार हुआ कि देश के प्रधान मंत्री जी का मत है कि यह मेरा प्रदेश है और आप यहां आईये व इंवैस्ट कीजिए। उसके अंतर्गत भी आज 240 योजनाएं धरती पर उतरी हैं। अनेकों योजनाओं पर काम हुआ। लगातार सरकार और विपक्ष अपनी-अपनी भूमिका निभा रहा है। विपक्ष का अपना काम है परन्तु ऐसी भूमिका भी न हो जाए कि जनता इनके मत को मानना ही बंद कर दे क्योंकि इसका फैसला देश व प्रदेश की जनता

28.02.2020/1200/SS-YK/4

करती है। हम जो मर्जी कहें कि हमने किया है और ये कह दें कि इन्होंने (सत्तापक्ष) कुछ नहीं किया है परन्तु उसका निर्णय कौन करेगा। उसका निर्णय तब हुआ जब धर्मशाला का बाई-इलैक्शन हुआ। दोनों सीटें भाजपा ने जीतीं और वहां कांग्रेस के प्रत्याक्षी की जमानत जब्त हो गई..

जारी श्रीमती के0एस0

28.02.2020/1205/केएस/वाईके/1

श्री राजेश ठाकुर जारी----

वहां मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की 4 सीटों पर हम फिर जीत कर गए और देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने धर्मशाला में आ कर हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री जी की पीठ को थपथपाया और कहा कि प्रदेश की जनता में जो आप काम कर रहे हैं, वह बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसका निर्णय जनता ने लिया और लगातार विकास का रथ आगे बढ़ रहा है। जैसे विकास बढ़ता है तो विपक्ष को अपने आने वाले समय में अंधेरा नज़र आने लगता है क्योंकि जनता-जनार्दन होती है और इस बार दिल्ली के फैसले में हमें वोट मत 9 परसेंट ज्यादा मिला। 15 साल कांग्रेस की सरकार वहां रही, ये ढाई परसेंट पर लुढ़क गए, यह भी देखने की बात है। देश में जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को रोकने के लिए अनेकों पार्टियां इकट्ठी हुईं, आज ऐसे हालात बन गए, उस 135 साल पुरानी पार्टी, जिसकी स्थापना ए.ओ.ह्यूम ने की थी, वह अंग्रेज अधिकारी थे और दूसरी ओर हम उस पार्टी के नेता हैं जिसको 70 साल हुए और जिसकी स्थापना आदरणीय डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और जिन्होंने अपना बलिदान कश्मीर में दिया और उनको वहां से अरैस्ट करके कश्मीर में बंद कर दिया गया और असली श्रद्धांजलि धारा-370 की या 35-ए की डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस दिन मिली जिस दिन वहां से यह कानून हटा। इस कानून को हटाने की पहल प्रधान मंत्री जी ने की। धारा-370 हटी, तीन तलाक के ऊपर कानून बना और राम मंदिर का मसला हल हुआ। ये बहुत बड़े फैसले थे जिसका मुद्दा ले कर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जाती थी। इस पर नारे भी बने हुए थे। यह काम हमारी सरकार ने किया है और आज हमारी सरकार का हाथी रथ आगे बढ़ रहा है। विकास की गति को ले कर पूरे देश और प्रदेश में चर्चा है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा सुशासन, प्रशासन दे रही है। विपक्ष के अंदर यह डर है कि आने वाले समय में फिर

हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमें कहीं विपक्ष में ही न बैठना पड़ जाए तथा 21 में से भी ये कितने रह जाएंगे यह आने वाला समय बताएगा।

28.02.2020/1205/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जब प्रदेश में कहीं भी दौरे पर जाते हैं तो जनता उनके आगे हजूम के रूप में खड़ी हो जाती है। हमारी रैलियां, हमारे कार्यक्रम, हमारे शिलान्यास व मुख्य मंत्री जी के उद्घाटनों का जनता तहेदिल से आभार व्यक्त करती है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनते ही पैंशन 80 साल से 70 साल कर दी। किसी ने ठीक कहा कि जब हाथी गांव में आता है तो सारे लोग उसकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार की बात है एक गांव में हाथी आया। वहां तीन व्यक्ति थे जिनको दिखाई नहीं देता था। वे भी हाथी को देखने चले गए। जब हाथी के पास पहुंचे तो एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और कहने लगा कि रस्सा है। दूसरा हाथी के शरीर से टकराया, उसने कहा कि यह तो दीवार है। तीसरे का हाथ हाथी के कान पर लगा तो कहने लगा कि यह तो पंखा है। इसी तरह से विकास विपक्ष के मेरे भाइयों को दिख नहीं रहा, वह हाथी विकास का रथ ले कर पूरे प्रदेश में चला है और विकास की गंगा बह रही है परन्तु इनका डर भी स्वाभाविक है। क्योंकि जिस पार्टी का 135 साल पुराना इतिहास हो और जिस पार्टी को आज ढाई परसेंट वोट मिल रहे हो, जिस पार्टी को आज नेता नहीं मिल रहा और जिस पार्टी का इतिहास बदल रहा है, तो इनका डर स्वाभाविक है। हमारी पार्टी और इनकी पार्टी में जमीन-आसमान का अंतर है। इनकी पार्टी विदेशियों द्वारा चलाई गई और हमारी पार्टी की क्रांतिकारी, आंदोलनकारी डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा नींव रखी गई। ये जितना मर्जी बोले, प्रदेश की जनता देख रही है। झूठ बोले कौआ काटे, ये गाना भी आपने सुना होगा। ये जितना मर्जी झूठ बोलें, झूठ बोलने पर काला कौआ ही काटता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.2.2020/1210/av-ag/1

श्री राजेश ठाकुर----- जारी

हमारे मुख्य मंत्री जी की जवाबदेही पर आज कोई शक नहीं है। मुझे तो हैरानी होती है क्योंकि हमें जब कांग्रेस के पदाधिकारी मिलते हैं तो एक बात की बधाई देते हैं और कहते हैं कि पहली बार जीतकर आए विधायकों को ऐसे मुख्य मंत्री मिले हैं। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है कि किसी भी नये विधायक के कोई भी काम नहीं रुकते। इसके लिए वे हमें बधाई देते हैं। मुझे एक और शेर याद आ रहा है :

अब समझे हम आपके दिल का दर्द, आपके चेहरे पर नज़र आ रहा है।
सरकार जय राम ठाकुर की विकास की ओर बढ़ रही है, और
आपका आधार खिसकता नज़र आ रहा है॥

राजनीति हमेशा आधार के ऊपर होती है और मुझे याद है जिस दिन जीतकर हम पहली बार विधान सभा के अंदर आए क्योंकि हमने पहले विधान सभा नहीं देखी थी। हम यहां विधान सभा के अंदर पहुंच गये। मैं यहां बैठा था तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने अपना भाषण दिया। ये कहने लगे कि मुख्य मंत्री जी, ऐसे लगता है कि इस सरकार का गियर, ब्रेक और स्टीयरिंग अलग-अलग व्यक्ति के पास है। जहां पर मुख्य मंत्री जी बैठते हैं मैं उठकर देखने लगा कि वहां पर कोई इंजन, गियर या ब्रेक तो नहीं है। मुझे वहां पर एक हेंडल नज़र आया क्योंकि पहले हमने विधान सभा नहीं देखी थी। अब सब कुछ मुख्य मंत्री जी के पास है और मुख्य मंत्री जी जो भी गियर डाल रहे हैं बड़ा सोच-समझकर डाल रहे हैं और आपको उसकी पीड़ा होना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूं कि मेरे ये भाई अगली बार फिर जीतकर आएं परंतु मैं यह नहीं बोल सकता कि इतना झूठ बोलने के बाद भी आप फिर से धरती पर खड़े हो जायेंगे। ऐसा समय फिर से नहीं आने वाला क्योंकि आज का समय और परिवेश

बदल चुका है। वह समय बीत गया जब आपने वर्षों तक लम्बा राज़ किया। वह समय बीत गया जब गांव में एक व्यक्ति होता था और वही ठेकेदार होता था तथा सारी वोटें उसी के कहने पर पड़ती थी। आज घर-घर में गृहिणी उज्ज्वला योजना तथा पेंशन योजना का लाभ

उठाया जा रहा है। हमने पहले सोचा ही नहीं था कि हमें गगरेट विधान सभा क्षेत्र से 22,000 वोट मिलेंगे। हर विधान सभा क्षेत्र व हर बूथ पर कांग्रेस हारी और परिणाम हमारी उम्मीदों से भी अच्छे आए। इसलिए आने वाला समय इनके लिए अनुकूल नहीं है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमें आपके ऊपर तरस आ रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपने एक्सीलरेटर को उठा दें और आने वाला समय आप लोगों के लिए भारी है क्योंकि जो तबदीली हो रही है यह आने वाले समय का भविष्य है। इसके ऊपर हमारा एक गीत भी है :

हम विजय की ओर बढ़ते जा रहें,
और
विपक्ष को पसीने पड़ते जा रहें।

इसलिए हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह विजय रथ हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी का है, यह रुकने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में प्रदेश में फिर से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और आप विपक्ष में ही होंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

समाप्त

28.2.2020/1210/av-ag/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भी धन्यवाद। आपने अपनी बात बहुत ही संक्षेप और निर्धारित समय में कही है। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि निर्धारित समय में ही अपनी-अपनी बात रखें।

अब मैं माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में हिस्सा लें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र में दिए गए अभिभाषण पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यहां पर पक्ष और विपक्ष की ओर से काफी अच्छी चर्चा की जा रही है। यहां पर जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ उसमें अनुच्छेद 370 को हटाने का ज़िक्र करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन उससे हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ने वाला है, उसी वक्त बादल जी की स्पीच आई और बादल जी ने लोक सभा में कहा कि हिमाचल से भी धारा 118 हटा दी गई है।

टी सी द्वारा जारी

28-02-2020/1215/TCV/AG/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर .....जारी

इसका असर हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, यह बात देखने की है? केन्द्र सरकार द्वारा जो कहा जाता है,उस पर हिमाचल प्रदेश को ज्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दी गई है और यह टिप्पणी आई है कि हिमाचल प्रदेश से भी

धारा-118 को हटा दिया जाये। चाहे यह टिप्पणी बादल या औवेसी ने की हो लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं तो इसका असर हुआ। जहां तक राम जन्मभूमि की बात है, राम जन्मभूमि कोर्ट का फ़ैसला था और पठानिया जी, फैसला यह था कि राम जन्मभूमि को ट्रस्ट में दिया जाये। राम जन्मभूमि को ट्रस्ट में देने का तो आपने स्वागत किया लेकिन आपकी सरकार बनते ही पहला फ़ैसला आया कि कुल्लू का रामचन्द्र ट्रस्ट ख़त्म किया जाये। ये दोगली बातें हैं। एक तरफ आप ट्रस्ट बनने का स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ सरकार बनते ही ट्रस्ट को ख़त्म करते हैं। आपकी ऐसी क्या विवशता है कि बने हुए ट्रस्ट को आप ख़त्म कर देते हैं। इसमें आपका दोगलापन नज़र आ रहा है। जनता के बीच में जाकर आपको इसका जवाब देना होगा। 'गुडिया हैल्प लाइन', 'होशियार सिंह हैल्प लाइन' इत्यादि बहुत-सी हैल्प लाइनें बनाई गईं परंतु गुडिया और होशियार सिंह को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं। एक चरानी को फंसाने के लिए सारा खेल रचा गया लेकिन इससे सरकार की बेबसी नज़र आ रही है। सरकार इतनी बेबस है कि उसे हैल्प लाइन-ही-हैल्प लाइन बनानी पड़ रही है। बहुत-सी योजनाएं बनाई जा रही है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। जैसे रेलवे स्टेशन में लिखा होता है कि 'रिश्ते-ही-रिश्ते', ब्याह-शादियां पता नहीं कितनी होती है? ऐसे ही यहां पर योजनाएं-ही-योजनाएं हैं। आप 'हिमाचल गृहिणी योजना' की बात करते हैं, यदि आप सच में गृहिणियों के हितैषी हैं तो आप सिलेंडर को सब्सिडाइज कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आपको मोबाइल तो फ्री है लेकिन चार्जिज़ हर महीने देने पड़ेंगे। 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' पूरी तरह से फेल होती नज़र आ रही है। मैं स्वयं लाभार्थी हूं। पहाड़ों की जो टोपोग्राफी है, यदि उस तरह से बाड़ को लगाते हैं तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कृषि मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, ये काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। इसमें लाभार्थी का जो शेयर रखा गया है,

28-02-2020/1215/TCV/AG/2

वह 30 प्रतिशत है और वह बहुत ज्यादा है। अगर हिमाचल के गरीब किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है तो उसको 10 प्रतिशत करना चाहिए। किसान अपने खेतों में

तो बाड़ लगा देता है लेकिन साथ में फॉरेस्ट लैंड होने के कारण या तो खेत का हिस्सा छोड़कर बाड़ लगानी पड़ती है या फॉरेस्ट वालों को समय-समय पर झाड़ियां काटनी पड़ेगी वरना उसमें शॉट-सर्किट हो जाएगा। इन सारी बातों का बजट में ख़्याल रखना चाहिए। मैं कुल्लू जिला की बात करना चाहूंगा। वहां पर भिड़ीबाई-बजौरा में एक गऊशाला बनाई गई थी। वह गऊशाला बह गई और

एन.एस. द्वारा जारी।

28-02-2020/1220/NS/AS/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर .....जारी

और इस बात को ऐसे छिपाया गया कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। माननीय मंत्री जी आप वहां पर गए और आपने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से गऊएं बहती देंखी फिर क्यों इस बात का छिपाया गया? क्या सरकार अपने अधिकारियों की कमियों को छिपाने के लिए है? वहां पर सैंकड़ों गऊएं मर गईं और आज तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई? हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। इससे सरकार की मानसिकता साफ़ नज़र आती है कि गौवंश के प्रति आप कितने गंभीर हैं?

अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख़ में मनरेगा की स्थिति ठीक नहीं है। आवास योजना में बहुत सारे बैकलॉग चल रहे हैं। यहां पर नील क्रांति की भी बात कही गई है। मैं कुल्लू के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। ट्राउट फिशिंग के बार में बोलना चाहूंगा। Trout is a delicacy. ट्राउट को पालने के लिए बहुत सारे उद्यमी आगे आए लेकिन पिछले दो वर्षों में पहली बार सीड जम्मू -कश्मीर से मंगवाया गया और उसमें वायरस आ गया। अध्यक्ष महोदय, दो सालों से लगातार ट्राउट के सीड में वायरस आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी जांच की कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि सारे-के-सारे तालाब खाली पड़े हुए हैं। अगर किसी उद्यमी को नुकसान होता है तो उसका इंश्योरैंस कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा ले लेती हैं। इसलिए ये योजनाएं धरातल में सफल नहीं हो पा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंश्योरैंस का प्रीमियम 22000 रुपये पर 2 लाख का है। अध्यक्ष महोदय, जो फीड की क्वालिटी सरकार

द्वारा दी जा रही है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। इन सब विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के ऊपर अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और एक समय में सारा राशन नहीं मिलता है। वर्ष 2013 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यह बात ठीक है कि इस योजना को आगे बढ़ाना होगा। कम-से-कम लोगों को राशन तो एक समय पर मिलना चाहिए। एक आदमी कितनी बार डिपू के चक्कर लगाएगा? आज तेल मिल रहा है, कल दाल मिल रही है और फिर कोई दूसरा सामान मिल रहा है। कीमतों में बार-बार बढ़ौतरी हो रही है। इस दस्तावेज़ में पंचायती राज को सुदृढ़ करने की बात कही गई है। जहां-जहां पंचायतें और पंचायत

28-02-2020/1220/NS/AS/2

समितियां थी तो वहां पर पंचायत समितियों और जिलापरिषद में पूरी कोशिश की गई कि राजनीतिक दखल दिया जाए। मेरे कुल्लू ब्लॉक में मुंह की खानी पड़ी और मेरा अपना सदस्य बना लेकिन उसके खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। यह भी राजनीतिक हस्तक्षेप था।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने नशे के ऊपर अपने विचार रखे हैं। इसके आंकड़े हर साल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और यह बहुत चिंता का विषय है। पिछले कल माननीय विक्रमादित्य जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमने उड़ता पंजाब तो देखा था लेकिन अब उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर परिवहन बसों के बारे में भी कहा गया है। गांव में बसों का यह हाल है कि अधिकतर रूटों पर ओवरलोडिंग चल रही है। बसें खड़ी हैं लेकिन वहां पर ओवरलोडिंग चल रही है। एडिशनल बसों की मांग हो रही है लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और बसें खड़ी हैं तथा जंग लग रहा है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर पर इलैक्ट्रिक बसें रोहतांग के लिए खरीदी गई थी और ये बसें बहुत महंगी खरीदी गई थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्हें समय पर उपयोग में क्यों नहीं लाया गया और रोहतांग के लिए समय पर क्यों नहीं चलाया गया?

आज इनमें से कुछ बसें मंडी को दे दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, शिमला और मनाली में ट्रेफिक कंजैशन को दूर करने के लिए अभी तक दो साल से अध्ययन ही किया जा रहा है। धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, "अमृत योजना" शिमला व कुल्लू में चल रही है और इसके तहत पार्किंग बनाने की व्यवस्था की गई थी। मैं कुल्लू के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा। सरवरी बस अड्डे के सामने एक पार्किंग प्रस्तावित थी और सर्वे में पार्किंग प्रस्तावित हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये पार्किंग कहां गायब हो गई और किसने इसे ड्रोप किया? वहां पर लगभग 50-60 लाख रुपये का पुल भी डाल दिया गया है लेकिन पार्किंग योजना से ही गायब हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके क्या कारण रहे हैं?

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.02.2020/1225/RKS/AS-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर... जारी

आज मेरा विषय ब्यास तटीयकरण की चिंता पर है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? इसके बाद हिम ऊर्जा की बात आती है। अध्यक्ष जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर देखा होगा कि जितना बड़ा घपला सोलर लाइट्स में हुआ है, उससे बड़ा घपला कोई नहीं हो सकता। तीन साल तक वे लाइटें जरूर चली लेकिन तीन साल के बाद वे सारी लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। आज वे लाइटें टिमटिमा रही हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इन लाइटों के लिए जो पैसा बर्बाद किया गया है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसी तरह एक 'पैनल टू ग्रिड स्कीम' थी। जिसमें पैनल से ग्रिड को जोड़ने का प्रावधान था और ग्रिड से स्ट्रीट लाइटें जलाई जानी थीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस स्कीम को क्यों ड्रोप किया गया? हिम ऊर्जा ने अभी तक कोई भी रेट कॉंट्रैक्ट नहीं किया है। मैंन 5-6 महीने पहले पंचायतों के लिए सोलर लाइट्स आबंटित करने हेतु हिम ऊर्जा को पैसे दिए थे। लेकिन मुझे 6 महीनों से यही जवाब मिल रहा है कि अभी हमारा रेट कॉंट्रैक्ट नहीं हुआ है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर सोलर लाइट खरीदी, जिसकी कीमत 4

हजार रुपये और 15 साल तक की गारंटी थी। जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो वहां उस लाइट की कीमत 18 हजार रुपये और तीन साल की गारंटी बताई जाती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप इस धांधली पर अंकुश लगाइए। हम बजट पर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में कितना पिछड़ गया है। मैंने पिछले शीतकालीन सत्र में हिमाचल प्रदेश की तुलना उत्तराखंड के साथ की थी लेकिन उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार 'पर्यटन नीति-2019' लेकर आई है लेकिन अभी तक यह नीति लागू नहीं हुई है। मैं उस पर्यटन नीति में पढ़ रहा था कि जो बिल्डिंग या मशीनरी होगी उसकी लागत तो शामिल की जाएगी लेकिन इसमें लैंड की कोस्ट शामिल नहीं की गई है। अगर कोई उद्यमी प्रोजैक्ट लगाना चाहता है तो उसे बिल्डिंग की कीमत से मंहगी तो भूमि पड़ेगी। जम्मू-कश्मीर में भूमि को सब्सिडी में जोड़ा जाता

28.02.2020/1225/RKS/AS-2

है लेकिन हिमाचल प्रदेश में लैंड वैल्यू को नहीं जोड़ा जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए।

टूरिज्म के क्षेत्र में जो आंकड़े मुझे मिले हैं उनके अनुसार इस क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया टूडे के सर्वे 'State of States Conclave' में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर पिछड़ गया है। इस वर्ष तो एक सप्ताह भी टूरिस्ट सीजन नहीं चला। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार कनैक्टिविटी में सुधार लाएं।

आज मंडी, शिमला और गगल के हवाई अड्डे का ज़िक्र हो रहा है लेकिन कुल्लू हवाई अड्डे की कोई बात नहीं की जा रही है। कुल्लू हवाई अड्डा सरकार की लिस्ट से गायब हो गया है। आप मंडी, शिमला में हवाई अड्डा बनाइए, गगल हवाई अड्डे का विस्तार कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे लेकिन आप कुल्लू के साथ भेदभाव मत कीजिए। जब नरेन्द्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आते हैं तो कुल्लू, बिजली महादेव की बात करते हैं। अगर उन्हें

हिमाचल प्रदेश से प्यार है तो आप केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये की प्रपोजल भेजिए। मोदी जी के लिए 500 करोड़ रुपये कौन-सी बड़ी बात है। आपको केंद्र से 500 करोड़ रुपये एकदम मिल जाएंगे लेकिन मुझे सरकार की नीयत में खोट लग रहा है। आपकी एक 'उड़ान' तो पहले ही फेल हो गई है। हिमाचल प्रदेश को बाकी राज्यों ने थीम राज्य बना दिया। वे हर वर्ष दूसरे राज्य को थीम राज्य बनाते हैं। सुरजकुंड वाले इससे अपनी कमाई करते हैं लेकिन उस कमाई का हिस्सा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता है। हमें तो अपने राज्य की थीम को प्रचारित करना होगा तभी यहां पर टूरिस्ट आएंगे। जो आपने इन्वैस्टर मीट की है उसमें टूरिज्म पर ज्यादा फोक्स देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । कीर्तपुर-मनाली हाइवे के लिए सरकार कोशिश कर रही है और मैं चाहता हूं कि इस हाइवे पर आगे भी अच्छा कार्य हो। सरकार की कीतनी नजर है

श्री डी.टी. द्वारा... जारी

28.02.2020/1230/DT/DC-1

श्री सुन्दर सिंहः जारी

सरकार कितने डयूरेशन में इसे मोनिटर कर रही है। कुल्लू में एक भारत माला का एक प्रोजैक्ट कुल्लू से मणिकरण के लिए था, वहां पर एक रोड का निर्माण होना था, उसका सर्वे भी हुआ। इसका श्रेय लेने के लिए पूर्व सांसद ने कहा कि यह मैंने किया, वर्तमान सांसद ने कहा कि यह मैंने किया। जब दो साल बाद हमने प्लानिंग विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत माला का तो कोई प्रोजैक्ट ही नहीं है। फिर जब हमने बाद में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको हमने हाईवे न0- 69 से जोड़ दिया। इन्होंने कुल्लू मणीकर्ण रोड को भी डाल दिया जिसका अभी सर्वे भी नहीं हुआ है। यह हमारे साथ धोखा हो रहा है। कुल्लू-शीलाभदाणी भूभू टनल इसकी फिजिबिल्टी का कंपनी द्वारा जो सर्वे हुआ था वह आज तक केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली महादेव के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसकी वाइडनिंग की जाए। इसकी लैंड एक्विजिशन हो गई है परंतु न जाने क्यों हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

जबकि मुख्य मंत्री की घोषणा तो एक फरमान होती है और इसमें अवश्य काम होना चाहिए। भूतनाथ ब्रिज का मुझे अब जवाब मिला कि यह ब्रिज पहली जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। तब तक तो हमारा टूरिस्ट सिज़न खत्म हो जायेगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि यह भूतनाथ ब्रिज को, जो इसमे ख़राबी आई, जो इसमें क्रेक आये, यह जिम्मेवारी किसकी तय की गई। इसमें जो तीन करोड़ का अतिरिकत खर्चा पड़ा है और लगभग 1.50 करोड़ रूपये का जो वैली-ब्रिज वहां पर बनाना पड़ा, उसकी लाईबिल्टी किस पर फिक्स की जाये। कम-से-कम किसी की तो जिम्मेवारी फिक्स की जाये ताकी पता चले की किसने ऐसा काम किया है। पिछले दो सालों में भुंतर ब्रिज पर भी किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा जबकि नैशनल हाई-वे की तरफ से इसके लिए पैसा मंजूर किया गया है फिर भी काम नहीं हो रहा। गरी-मलाणा रोड, शारनी रोड पर कोई काम नहीं हो रहा। कुल्लू के ढालपुर में इण्डोर स्टेडियम बनना था उसका काम अभी तक शुरू किया गया। कुल्लू बिल्डिंग हैड का पैसा इधर-उधर शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूलों की बिल्डिंग का पैसा दूसरे जिलों को दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग का रिपेयर एण्ड मैंटेनैंस का पैसा, जो मेरी विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ, वह कहीं और जा रहा है। PWD का Project Implementation Unit मेरी विधान सभा से शिफ्ट हो गया है और माननीय जल

28.02.2020/1230/DT/DC-2

शक्ति मन्त्री जी , आप बहुत शक्तिशाली मन्त्री हैं, आप सच में प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा की जल शकित तो टीम में होनी चाहिए। आप कुछ सोचें, कुल बोलें उसको धरातल में लाने के लिए तो अफसरशाही ने काम करना है। कुल्लू की कुकल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कृप्या करके इसे आगे बढाईये। हमारे यहां मलाणा,ग्रान व रसोल में स्कूल खाली चल रहें हैं। एच0आर0डी0 मन्त्रालय की एक पॉलीसी है कि हर ज़िले में सैन्टरल स्कूल बनेगा। कुल्लू में सैन्टरल स्कूल क्यों नहीं बन रहा? यह भी ज़िला कुल्लू के साथ भेदभाव है। कुल्लू हस्पताल के बारे में मैं कल भी बोल चुका हूं। उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बात है जो कुल्लू से फीड बैक आ रहा है उसमें कुल्लू के हस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। आपने कहा की आयुर्वेद के नेचर पार्क बन रहें हैं, मैं

इसका स्वागत करता हूं की जगह-जगह नेचर पार्क बन रहें हैं। फारेस्ट वालों को ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क पर अभी और काम करने की जरूरत है। ढालपुर मैदान का चीर हरन हो रहा है। कुल्लू में हमारे पास एक ही मैदान है, उस पर बाढ़ लगा-लगा कर उस मैदान को खराब किया जा रहा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा की हमारे ज़िला कुल्लू के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव के लिए चाहे हमारे ज़िले से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्री हो या अन्य विधायकगण हो, यह सभी चुपचाप मौन धारण कर बैठे हैं

श्री एन.जी. द्वारा जारी

28-02-2020/1235/डी.सी.-एन.जी./1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जारी.....

कुल्लु के लाड्डा में 22 करोड़ रुपये unspent पड़ा है। कुल्लु में केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल रहा है, अस्पताल के बुरे हाल हैं, एयरपोर्ट और रास्तों के बुरे हाल हैं। कुल्लु एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें मैडिकल कॉलेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि यह सरकार जाग जाए, शीर्ष पदों पर आज हिमाचली अफ़सर बैठे हैं जिनकी हिमाचल के प्रति अच्छी सोच है और उनके साथ एक टीम के रूप में कार्य करें। यदि हम इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धरातल पर नहीं लाऐंगे तब तक यह सारी बातें हवा में ही रह जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण सत्य से परे है, धरातल पर जो कुछ हो रहा है उन बातों का व्याख्यान इसमें नहीं किया गया है इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

28-02-2020/1235/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्षः धन्यवाद, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी। अब माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण इस माननीय सदन में दिया है उससे यह साफ लगता है कि पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। इन दो सालों में हिमाचल प्रदेश ने 'सबका साथ, सबका विकास' के तहत विकास की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले कल से इस पर चर्चा हो रही है और विपक्ष की ओर से जो सदस्य चर्चा कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत हैरान हूं। माननीय श्री मुकेश जी और माननीय विक्रमादित्य जी ने पिछले कल बड़े जोरों-शोरों से कहा कि सरकार नेशनल हाईवे बनाने जा रही थी उनका क्या हुआ? मण्डी का एयरपोर्ट बन गया क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट बनाना क्या किसी गांव में पैदल रास्ता बनाने जैसा काम है? विधायक निधि से 1-1.5 लाख रुपये दिया और रास्ता बना दिया गया लेकिन उस रास्ते को बनाने में भी 2 वर्ष का समय लग जाता है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने 70 सालों में हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे औरएयरपोर्ट बनाए हैं।...(व्यवधान) कितने फोर-लेन आपने हिमाचल प्रदेश में बनाए।...(व्यवधान) जितने भी नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने कमिटमेंट किए हैं उनका एक प्रोसेस होता है और उसके तहत डी.पी.आर. बनती है, पैसा स्वीकृत होता है उसके बाद उनको बनाने के लिए समय लगता है। आप केवल 2 साल में पूछ रहे हैं कि 60 नेशनल हाईवे बन गए क्या? मण्डी में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब इतना आसान है कि केवल 2 वर्षों में बन जाऐंगे।...(व्यवधान) आने वाले समय में आपके सामने ही बनेंगे।...(व्यवधान) आपके कहने से आज बन जाऐंगे क्या?...(व्यवधान)

28-02-2020/1235/डी.सी.-एन.जी./3

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण कृपया बैठे-बैठे न बोलिए।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आंकड़े बता रहे हैं कि 2 साल में सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। आप और हम दोनों झूठ बोल सकते हैं परन्तु आंकड़े झूठे नहीं हो सकते। overall development के लिए India Today का एक सर्वे हुआ जिसमें हिमाचल प्रदेश आज के समय में नम्बर-2 पर है और शिक्षा व हैल्थ के क्षेत्र में नम्बर-1 पर है।...(व्यवधान) यह हम नहीं India Today का सर्वे कह रहा है।...(व्यवधान) आपके समय में 8वें-10वें पोज़िशन में थे और हम केवल 2 सालों में इस स्थान पर आए हैं।...(व्यवधान)

Sh. Vikramaditya Singh : We had got award for best primary education in the Country. ...(interruption)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण कृपया बैठे-बैठे न बोलिए। माननीय ठाकुर जी आप केवल चेयर को सम्बोधित कीजिए।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः इन्होंने फर्जी डिग्रियों का मुद्दा उठाया और मैं इनकी बात से सहमत हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्षः मैं फिर से कह रहा हूं कि माननीय सदस्यगण कृपया बैठे-बैठे न बोलिए।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अगर कहीं पर क्राइम होता है

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2020/1240/JK/HK/1

श्री नरेन्द्र ठाकुरः-----**जारी**-----

और फर्जी डिग्री का कोई मामला सामने आता है तो उनके उपर एक्शन होना चाहिए। मैं हैरान इसलिए हूं कि पेपर में बात आती है कि यहां पर फर्जी डिग्रियों का मामला पकड़ा गया। ये कहते हैं कि पेपर की स्टेटमैंट के ऊपर ही केस दर्ज़ कर दो। अरे, इसमें भी कोई

प्रोसिज़र है। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो कम-से-कम यहां पर तैयारी करके तो आया करो। अगर केस किसी के ऊपर दर्ज़ करना है । ...(व्यवधान) Sir, I am addressing the Chair but they are not addressing the Chair. इसलिए इनको कहो कि ये बात को सुन लें। पहले उसके ऊपर इन्वैस्टिगेशन होती है। प्राइमरी इन्वैस्टिगेशन का केस बनता है, फिर एफ.आई.आर. होती है और उसके बाद अरैस्ट किया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि पेपर में बात आई है whether it is authentic or not. पेपर की हर बात सच नहीं होती है। उसमें इन्क्वायरी में पता चलेगा। अगर वहां पर फर्जी डिग्री का कोई ऐसा केस है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने डायरैक्शन दे दी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिए। आप लोग बैठे-बैठे न बोलें। श्री नरेन्द्र ठाकुर जी आप चेयर को अड्रैस करें और बात को आगे बढ़ाएं।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, इस इशू पर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अगर वहां पर कोई ऐसा घपला हुआ है तो वह पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यहां पर 15वें वित्तायोग के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। यह भी इनको चुभ रहा है। 45 परसेंट पिछले साल से हाइक और 11,431 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मिली है। लेकिन यह बात इनको हज़म ही नहीं हो रही है। ...(व्यवधान) ये नहीं चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, हमने कहां पर मना किया है लेकिन यहां पर जो बढ़ौत्तरी हुई है उसको भी आप एप्रिशिएट कीजिए। आप इसको क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? यह अनुदान राशि मिलने से हिमाचल प्रदेश का विकास होगा लेकिन आप इस बात को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। 45 तो आपके पास

28.02.2020/1240/JK/HK/2

एम.सी., म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं और दो नगर निगम हैं, उनके विकास के लिए यदि 260 करोड़ रूपया वित्तायोग से मिलता है तो यह हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात है। लेकिन यह बात भी आप लोगों को हज़म नहीं हो रही है । आप नहीं चाहते कि इस प्रदेश का

विकास हो। आज हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, it is your duty. आपने 70 साल इसके ऊपर राज किया और आज प्रदेश जो कर्ज़े में डूबा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का है। 18,000 करोड़ से 38,000 करोड़ तक आपने कर्ज़े में हिमाचल को पिछले पांच सालों में पहुंचाया। इसलिए आज जिस बात को आप यहां पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। ...(व्यवधान) आप सुनिए, जब धर्मशाला में इन्वैस्टर मीट हुई है, वह भी आपको हज़म नहीं हो रही है। क्या वह बुरी बात है कि बाहर का इन्वैस्टर हिमाचल प्रदेश में अपना करोड़ों रूपया लगा कर इन्वैस्टमैंट करें और हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले? हमने जो 97 हजार करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन किए हैं और 376 एग्रिमैंट हमने साइन किए हैं। जरुरी नहीं है कि सारे-के-सारे ही धरातल पर उतर जाएं। अगर 50 या 70 परसेंट भी उतरेंगे और हमने 2 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है उसमें से यदि 1 लाख लोगों को भी नौकरी मिल जाए तो क्या उससे स्टेट का भला नहीं है, उन बेरोजगारों का भला नहीं है? हमने दो महीने के अन्दर-अन्दर ही 13,656 करोड़ की 240 परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं, क्या यह स्टेट के लिए बुरी बात है? आप इस बात को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कम-से-कम जो सच बात है उसको तो आप एप्रिशिएट करिए। क्रिटिसाइज़ करना आपका फ़र्ज है। आप करिए लेकिन तथ्यों के आधार पर करिए। जो मुंह में आ रहा है, वही बोले जा रहे हैं कि यह सरकार ऐसी है, वैसी है। यह तो फैक्चुअल पोजिशन है। यह सरकार नहीं जाएगी और श्री जय राम ठाकुर जी बार-बार मुख्य मंत्री रहेंगे और आप लोग वहीं रहेंगे। मेरी एक बात और सुनिए। श्री विक्रमादित्य सिंह और श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी भी ड्रग्ज़ अडिक्शन के बारे में बोल रहे थे। यह ठीक है कि ड्रग्ज़ अडिक्शन जो स्टेट में है, वह बहुत बुरी बात है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

28.02.2020/1245/SS-HK/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर क्रमागत :

हमारा जो युवा है वह दिन-प्रतिदिन ड्रग्स एडिक्ट हो रहा है लेकिन यह चला कहां से था? मेरी बात सुन लो, सबसे ज्यादा नशे का प्रचलन 2012 से 2017 तक हुआ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मानीय सदस्य कृपया बैठे-बैठे न बोलें। जब आपकी बारी आयेगी तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नशा पिछली सरकार के समय में पूरी चरमसीमा पर था। ये कह रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है जबकि हम तो नशे को कम रहे हैं। दो सालों में हमारी सरकार ने 900 किलो चरस और 20 किलो चिट्टा पकड़ा है। इस नारकोटिक्स ड्रग्स ऐक्ट में हमने अमैंडमैंट करके बेल प्रोविजन को भी सख्त किया है। ...(व्यवधान) प्रोविजन हुआ है। क्या आपको पता नहीं है कि इसकी नोटिफिकेशन हुई है? ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लो, हमने प्रावधान तो किया है और नोटिफिकेशन भी आ जायेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पांच सालों में नशे को कम करने के लिए क्या प्रयास किये। आपने क्या किया, वह बताईये। अध्यक्ष जी, इनके समय में एक साल में 5 हजार नशीली गोलियां और 90 हजार नशीले कैप्सूल स्मगल होते थे। यह इनकी बिक्री का आंकड़ा था। यह आंकड़ा हमारी सरकार में आधे से कम रह गया है। हमने 500 केसिज़ रजिस्टर्ड किये। आपने तो केसिज़ क्या रजिस्टर करने थे लेकिन हमारे पास ऐसे फैक्ट्स भी हैं कि आप ही के लोग इस नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार बड़े लार्ज स्केल पर इस ड्रग्स को कम करने की कोशिश कर रही है।

अध्यक्ष जी, इस मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक जल मिशन योजना केन्द्र से आई है। इनको (विपक्ष को) उसमें बड़ी तकलीफ हो रही थी। कल मुकेश अग्निहोत्री जी इसके बारे में बड़े फ्यूरिअस होकर बात कर रहे थे। अरे भाई, आप सच्चाई को पचाना सीखिये। झूठ बोलने से कुछ नहीं हो जायेगा। ...(व्यवधान) मेरी बात सुनो, 2896 करोड़ रुपये से 337 योजनाओं की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दी है और वे धरातल पर उतरी हुई हैं। इसके मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं। हर घर में किचन के अंदर जाकर हम पूरे परिवार के लिए नलका लगायेंगे परन्तु आप नहीं चाहते हैं कि यहां पर हर परिवार को पानी मिले। यह हमारी केन्द्र और हिमाचल सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी

और जल शक्ति मंत्री, महेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी कंस्टिच्यूंसी में 38 करोड़ रुपये का फाउंडेशन स्टोन इस स्कीम के तहत रखा और उसका काम अवार्ड होने के बाद शुरू हो गया है। 30 हजार लोगों को घर-घर में पानी मिलेगा। ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लो, 30 हजार लोगों के घर-घर में पानी आयेगा, इससे दो साल पहले उन 14 पंचायतों की क्या हालत थी, वह मुझे पता है। गर्मियों में वहां पर एक बूंद पानी नहीं आता था। आप इस बात को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि घर-घर नलका लगे और 24 घंटे लोगों को पानी मिले। अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो आप खड़े होकर बोलिये। अगर आप चाहते हैं तो आप इस स्कीम को एप्रीशियेट कीजिए। मैं यहां पर ज़िक्र भी करना चाहूंगा, वैसे इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग कहां से बातें निकाल कर ले आते हैं। अब यह गृहिणी सुविधा योजना है क्या यह ठीक नहीं है? आप बोल दीजिए कि ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लो। हर घर में गैस का चूल्हा फ्री दिया और कहने लगे कि सिलेण्डर का दाम बढ़ गया।

जारी श्रीमती के0एस0

28.02.2020/1250/केएस/वाईके/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी---

अध्यक्ष जी, पिछले साल हमने 1,75,000 परिवारों को फ्री में गैस के चूल्हे दिए और 57 करोड़ रुपये की राशि इस पर व्यय हुई। इनके समय में पिछले पांच साल में री-इम्प्लॉयमेंट पर और एक्सटेंशन पर 38 करोड़ रुपये व्यय हुए जो कि आपने फिज़ूलखर्ची की। लोक कल्याण की योजनाएं, जिनका गरीब लोगों को फायदा होता, ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए थीं लेकिन यह आपकी सोच नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठे-बठे न बोलें। ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा योजनाओं का ज़िक्र नहीं करुंगा, मैं एक छोटा सा प्वाइंट लेने जा

रहा हूं कि इन दो सालों में हमारी सरकार ने एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्ज़ की लगभग 900 सीटों और अप्पर स्टडी के लिए 253 सीटों का प्रदेश में प्रावधान किया। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः विनय कुमार जी, बैठे-बैठे न बोलें। जब आपको मौका दिया जाएगा तो आप अपनी बात रखें। आप हमें सूची भेज दें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः पिछले साल लगभग 538 डॉक्टर, पैरा मैडिकल 311, स्टाफ नर्सिज़ 256, एम.एच.डब्ल्यू. 81, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को मिलाकर 728 पोस्टों की अप्वाइंटमैंट हमने की। हिमाचल प्रदेश में दो साल की पोजीशन देखें तो शायद आज कोई भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां एम.बी.बी.एस. डॉक्टर न हो। ...(व्यवधान) मैं आपसे हमीरपुर और सुजानपुर की बात कर रहा हूं। राजेन्द्र राणा जी आज बैठे नहीं हैं, जब दो साल पहले प्रदेश में हमारी सरकार आई थी तो हमीरपुर में 16 ही डॉक्टर थे और पूरे जिला में एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था। आप आंकड़े निकाल कर देख सकते हैं लगभग 126 डॉक्टर तो हमारे जोनल हॉस्पिटल और मैडिकल कॉलेज में हैं। इसका सारा श्रेय मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

28.02.2020/1250/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष महोदय, कल ये एक पेपर की न्यूज़ ले कर आए थे, पता नहीं उसमें फैक्चुअल पोजीशन क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा लेकिन राणा जी खुद ही कह रहे थे कि वहां पर 7 डॉक्टर हैं जबकि मैं वहां पांच साल रहा केवल एक या दो डॉक्टर से ज्यादा कभी भी वहां पी.एच.सी. या सी.एच.सी. में नहीं आए। इसलिए इन बातों की आपको तारीफ़ करनी चाहिए थी। मैं अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो हमारे दो साल की कारगुज़ारी हाउस के सामने रखी है, यह आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

28.02.2020/1250/केएस/वाईके/3

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Rakesh Singha (Theog): Speaker, Sir, I rise to express my views on the Governor's Address made in this House. अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को समझते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पेश किया है, यह असल में आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। पिछले एक वर्ष में जो सरकार ने शुरू में कहा था, जिस समय इस सदन के अंदर बजट पेश किया था,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

28.2.2020/1255/av-yk/1

श्री राकेश सिंघा----- जारी

और उसमें जो लेखा-जोखा दिया था कि सरकार क्या करना चाहती है; यह उसकी समीक्षा की एक रिपोर्ट है। यह एक किस्म से एनालिसिस है कि आप क्या कर पायें और क्या नहीं कर पायें। ऐसे दस्तावेज़ में मैं समझता हूं कि वह सब्जैक्टिव नज़रिए से नहीं होने चाहिए। वह ऑब्जैक्टिव ट्रुथ है, क्या है; उसको अगर इस दस्तावेज़ में दर्शाना हो तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस दस्तावेज़ के अंदर जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय का रहा है इसमें अधिकतर बातें सब्जैक्टिवली रिकॉर्ड की गई और सच्चाई को छिपाने का काम किया गया है। यह दस्तावेज़ जिस समय बन रहा था मुझे यह अहसास होता है कि यह जो लगभग 50 पेजिज का दस्तावेज़ बना; यह बन नहीं पा रहा था। विभागों को आदेश दिए गए कि और रिपोर्ट कार्ड लाओ। विभागों ने जब अपने-अपने रिपोर्ट कार्ड दिए तो उनमें ऐसी-ऐसी बातों का भी ज़िक्र कर दिया गया जिसके बारे में मैं समझता हूं कि वे विभागीय स्तर की अचीवमैंट्स में भी शामिल नहीं होनी चाहिएं। आप जब इस दस्तावेज़ में जायेंगे तो इसके पैरा 21 में देखिए। सरकार कहती है कि 30,000 वर्ग मीटर। कहने के लिए 30,000 वर्ग मीटर; परंतु यह है क्या? यह केवल तीन हैक्टेयर बनते हैं जिसमें सरकार ने प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन की है; यह आपने कौन-सा कीर्तिमान स्थापित किया है?

3 हैक्टेयर पर तो एक किसान कल्टिवेशन कर लेता है और हमारी पूरी सरकार यह दिखाना चाह रही है कि हमने बड़ी भारी अचीवमैंट प्राप्त की है। यही नहीं, आप पैरा 22 को देखिए जिसमें लिखा है कि 40 मशरूम उत्पादकों हेतु मशरूम प्रोडक्शन यूनिट्स खड़े कर दिए; यह आपने कौन-सी बड़ी भारी अचीवमैंट प्राप्त कर ली? यहां पर मंत्री महोदय अभी बैठे नहीं है, इन्होंने चार रेड सिंधी गाय लाई और उसको भी अचीवमैंट में डाल दिया। इसका ज़िक्र पैरा 25 में किया गया है। आगे पैरा संख्या 38 में आपने कहा है कि 500 ग्राम चीनी प्रति सदस्य दी गई और हर महीने देते हैं। जबकि वह भी हर महीने नहीं मिल पाती। यह 500 ग्राम चीनी की क्या अचीवमैंट है? मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी-ऐसी बातों को बजट में दर्शाने की क्या ज़रूरत थी? इसके आगे पैरा संख्या 53 में कहा गया है कि मण्डी जिला के पधर में एक फायर पोस्ट क्रिएट की गई। क्या इन चीजों को अचीवमैंट में

28.2.2020/1255/av-yk/2

डालने की ज़रूरत है? आगे चलिए, शिक्षा मंत्री महोदय ने तो कमाल ही कर दिया और सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। इन्होंने पैरा संख्या 94 में कहा है कि दो प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण किया गया, then what is the achievement of the Government? यह बात सही है कि जब आपने इस अभिभाषण को शुरू किया तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसमें सही एनालसिस दिए गए। इस दस्तावेज़ के जैसे पैरा संख्या 5 में दिया गया है कि "Public service and good governance are the main objectives of my Government". किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व जो संविधान से चलता है वह जनता को अच्छी सेवाएं देना होता है। लेकिन मुझे यह सरकार बताए कि क्या इस सरकार के अंदर कोई दैवीय शक्ति है कि वह सेवाएं प्रदान कर देगी। क्या सेवाएं हैं? आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क इत्यादि की सेवाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ये सेवाएं तभी प्रदान हो सकेगी अगर सेवादार भी होंगे। अगर सेवादार ही नहीं होगा तो अभी जो चम्बा के हाल बताए और दूसरी जगह भी यही हाल है; बगैर अध्यापक के ये केवल

दो स्कूल ही नहीं है। इसके बारे में तथ्य सही तरीके से नहीं रखे जाते, मैं उनको अब पेश कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए---

टी सी द्वारा जारी

28-02-2020/1300/TCV/AG-1

श्री राकेश सिंघा....जारी

ये जो तथ्य हैं ये नीति आयोग से हैं, ये आपके विभागों से लिए गए हैं। आप स्वयं हाल देख लीजिए, आपके हाल क्या है? उससे पता चलेगा कि हमारा जो उद्देश्य good governance or public service को प्रदान करने का है, क्या हम उसको प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं। हां, यह दूसरी बात है कि without this staff कि अगर Head of the Departments और हमारे Secretaries यदि आपने उनको दैवीय शक्ति दे दी है तो ये सेवाएं इस स्टॉफ को निकाल करके भी प्रदान हो जाएगी लेकिन यह संभव नहीं है, न किसी को दैवीय शक्ति दे पाएंगे और न ये गुड सर्विसिज़ संभव हैं। आपके हैल्थ विभाग का क्या हाल है, हैल्थ विभाग में Staff Nurses 29 per cent vacancy; Pharmacist 48 per cent vacancy; Medical Lab Technician, Grade II - 64 per cent vacancy; Laboratory Assistant - 66 per cent vacancy; Operation Theatre Assistant - 66 per cent vacancy; Supervisors - 23 per cent vacancy; Male Health Worker - 68 per cent vacancy; देहात में आप कह रहे थे, ठाकुर साहब कहां है, शायद चले गये हैं। इसमें जो PHCs in rural areas उनके हालात दे लीजिए तो वहां पर डॉक्टर्ज़ की 32 वैकेंसिज कम हैं जो रूरल एरियाज में पी0एच0सीज हैं। Pharmacist की 50 per cent vacancy rural area में है; Nursing Staff की 67 per cent vacancy है , Male Health Worker की 68 per cent vacancy है फिर हम कह रहे हैं कि हम पूरी हैल्थ सुविधाएं दे रहे हैं। यह कैसे संभव है? with all this vacancy. Is it possible? यह संभव नहीं है। यह किसी चुनी हुई सरकार का फोकस होना चाहिए लेकिन आपको इनकी चिंता नहीं है। यह

सिर्फ वैकेंसीज हैं। आपने जो 2 स्कूल बनाये हैं, उनको इसमें नहीं गिना गया है और जो नये स्वास्थ्य संस्थान खोले या अपग्रेड किए गये हैं, उनको भी इसमें नहीं गिना गया है। probably ये वैकेंसीज 2015 की पॉजिशन्ज से है अगर आज की वैकेंसीज को लिया जाये then it will even be higher. सिर्फ इस विभाग के हाल इस तरह के नहीं है, बिजली विभाग में Junior Engineers - 64 per cent vacancy; आप बताएं कि आप कैसे बिजली प्रदान करेंगे? आप पहाड़ों में कहीं भी चले जाइये, आप चौपाल, ठियोग, किन्नौर और आनी कहीं भी चले जाइये थोड़ी-सी

28-02-2020/1300/TCV/AG-2

बारिश, हवा या बर्फ पड़ जाये तो कई महीनों तक बिजली नहीं आती है। इनके कुल्लू में भी यही हाल है। It is not possible with this staff. Lineman - 24 per cent vacancy; Assistant Lineman - 51 per cent; Fitter - 35 per cent; Team Mate जो मेन है जो बिजली को रिस्टोर करेगा 81 per cent vacancy; or Junior Health Station - 98 per cent vacancy; आप कैसे बिजली प्रदान करोगे, आप मुझे बताइये। यदि आप इरिगेशन विभाग में देखेंगे तो इसमें भी इसी तरह से बुरे हाल हैं। जो Assistant Engineers -19 per cent vacancy; Junior Engineers - 22 per cent vacancy; Senior Assistant - 36 per cent; Pump Operator - 18 per cent; Pump Attendant - 31 per cent; Fitters - 27 per cent; ये है आपके हाल और यदि मैं विभाग कोड करूं तो उनके भी इतने ही बुरे हाल हैं। यदि हम एग्रीकल्चर को लें तो हमारे ADOs 58 per cent vacancy; Agriculture Extension Officers - 57 per cent vacancy; हॉर्टिकल्चर में जायें तो HDOs - 47 per cent vacancy; और AHDOs - 20 per cent vacancy ...(व्यवधान) अगर मैं ये गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ़ प्रिविलेज़ मोशन ले आएं, बिल्कुल मेरे खिलाफ़ प्रिविलेज़ मोशन लेकर आएं। ये मैं आपको तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, नीति आयोग व सब विभागों की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं।

एन.एस. द्वारा जारी।

28-02-2020/1305/NS/AG/1

श्री राकेश सिंघा .....जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार का second biggest failure आप वह भी सुन लो। आपका second biggest failure सरकार का है आप पूरे वर्ष एफ0आर0ए0 जो वहां पर फंसा हुआ है उसको रीमूव नहीं कर सके। आप कोर्ट में तथ्य ही पेश नहीं कर सके। आप क्या करते रहे? आपने लाखों रुपये अपने खज़ाने से वकीलों को दे दिए लेकिन एफ0आर0ए0 के खिलाफ़ जो स्टे आया है उसको रीमूव नहीं कर सके। आप इसके बारे में कुछ आंकड़े सुने लें जो मैं यहां पेश करने जा रहा हूं। एफ0आर0ए0 के तहत जो पेड़ आए हैं और वर्ष 2014 से वर्ष 2019 मार्च तक एफ0आर0ए0 के तहत जो कटान हुआ है वह किस प्रकार से है और आप यह बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह सके। हमारी अलग-अलग एक्टिविटीज़ एफ0आर0ए0 के तहत आती हैं और इसमें एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। कुल पेड़ जो कटे हैं वे महज़ 17,327 कटे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट के निर्माण में 80,000 पेड़ कट गए। हाईवेज़ में जो पेड़ कटे हैं और यह एफ0सी0ए0 के तहत आता है तथा इसमें 83,000 पेड़ काटे गए हैं। 1959 एक्टिविटीज़ एनिमल हसबैंडरी, कम्युनिटी सैंटर्ज़, इलैक्ट्रिक लाइन्ज़, हैल्थ सैंटर्ज़ और रोडज़ की भी आती हैं तो सिर्फ 17,327 पेड़ कटे हैं। ---(व्यवधान) आप सुन लो। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी, प्लीज़ वाइंड अप करें। आपका निर्धारित समय पूरा हो रहा है। सभी सदस्यों को पूरा समय दिया है और आपको भी पूरा समय देंगे।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मैं "मुख्य मंत्री हैल्पलाइन " के बारे में बोलना चाहूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि इस हैल्पलाइन में कोई शिकायत करता है सूपी और इसका शिकायत क्रमिक नम्बर 109843 है। शिकायतकर्त्ता सत पाल सिंह 132482 है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह वह पंचायत है जो सांसद आदर्श पंचायत, बालीकोटी adopted by Shri J.P. Nadda, मेहरबानी करके माननीय जे0पी0नड्डा जी को बदनाम मत करो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पंचायत में यह शिकायत लगी है और ऐफिडेविट फाइल करने के लिए लोग तैयार हैं। कोई पैसा धरातल पर नहीं लग रहा है और

कहीं दूसरे खातों में जा रहा है। मनरेगा, स्वच्छ भारत, शौचालय आदि बनाने का पैसा कहीं और जा रहा है।

28-02-2020/1305/NS/AG/2

शिकायतें की लेकिन "no action" क्योंकि प्रभावशाली लोगों पर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बता दूं कि आने वाले समय में कठिनाई होगी। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को इस बात से समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं गुड़िया के बारे में भी कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मेहरबानी करके उसके माता-पिता री-इन्वैस्टिगेशन करने के लिए कह रहे हैं तो आप कीजिए। आपको री-इन्वैस्टिगेशन करने के लिए कौन रोकता है? कानून में री-इन्वैस्टिगेशन का प्रावधान है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके कर लें। अंत में, इस दस्तावेज़ में आपने जहां से शुरू किया है, वह तथ्य आपके सही करना चाहता हूं। This will go into the records. आप गलत डाटा इसमें पेश कर रहे हैं ये आपको किसने बता दिया कि Article 370 has been abrogated. आपने धारा-370 का क्या किया? धारा-370 को इन-ओपरेटिव किया है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.02.2020/1310/RKS/AS-1

श्री राकेश सिंघा... जारी

लेकिन आपने कह दिया कि हमने एब्रोगेट कर दिया। आपको इसे एब्रोगेट करने के लिए किसने ताकत दी? मैं आज भी दावा करता हूं कि it will be restored by the Hon'ble Supreme Court. यह सौ प्रतिशत रिस्टोर्ड होगा। आप स्वेच्छा के आधार पर क्या कर सकते हैं? यह 35-ए है और यह आज का नहीं है। यह 35-ए वर्ष 1927 का है। आज हमने 118 रखा है। बहुत-से राज्यों ने जिसमें नार्थ ईस्ट के राज्य हैं, आन्ध्र प्रदेश है, जो 371 के आधार पर आज सारी नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं, आप उनको कैसे रोकोगे? You must have the Constitutional power to do it. जब उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं

कर सकते हैं? इसलिए यह बातें विवाद की मत बनाओ। यह देश एकमत से चलेगा, यह हाउस एकमत से चलेगा। यह डंडे के जोर पर नहीं चल सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली में हो गया है, it is very unfortunate. मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। इसमें दोनों समुदायों के लोग मारे गए हैं। हिन्दु भी मरे हैं और मुसलमान भी मरे हैं। मुल्क को चलाने का यह जो तौर-तरीका है मेहरबानी करके do not do it. यह हमारे बुजुर्गों का मुल्क है। यह शहीदे आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का मुल्क है। वे मुल्क के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और इस मुल्क को अगर हम इस तरह से तबाह करेंगे तो मैं समझता हूं this will be the most unfortunate part of the history. कृपया करके यह बात केंद्र सरकार को भी बता दो कि यह देश इस तरह से नहीं चल सकता। यह मुल्क सबका है। इसलिए इस मुल्क को संविधान के आधार पर चलाना होगा। यह किसी की मर्जी के आधार पर नहीं चलेगा। यहां गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। यह मॉडल जो आप दिल्ली में लागू करना चाहते थे,उसने तबाही कर दी है। इसलिए उस न्यायाधीश ने बिल्कुल सही कहा, I will not allowed 1984 riots in Delhi. बेसक उसकी ट्रांसफर हो गई लेकिन मैं उसकी दाद देता हूं। He took his due Judicial position which I feel any Judicial official should have taken at that time. अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक अपराह्न 2:10 बजे तक भोजनोवकाश के लिए स्थगित की जाती है।

सदन की बैठक दोपहर के भोजन के उपरान्त 2.10 बजे पुनः आरम्भ हुई

28.02.2020/1410/DT/DC-1

अध्यक्षः अब राज्यापाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए माननीय सदस्य, किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेगे।

श्री किशोरी लालः(आनी) माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहीम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2020 को जो अभीभाषणा इस माननीय सदन पर दिया गया, उस विषय में श्री बलबीर सिंह द्वारा जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी द्वारा उसका समर्थन किया गया है, मैं भी इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा

हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय हमारी प्रदेश सरकार को बने हुए 2 वर्ष का समय हुआ है और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मन्त्री, माननीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। जिस ढंग से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और पूरे प्रदेश में जिस ढंग से विकास हो रहा है, बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

28-02-2020/1415/डी.सी.-एन.जी./1

श्री किशोरी लाल जारी.....

इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का नाम ऊंचा हुआ है। यह बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा कर, 3 तलाक जैसी कुरीति को समाप्त करके, श्री राम मन्दिर का निर्माण और बहुत सारे सराहनीय कार्य केन्द्र की मोदी सरकार ने किए हैं जिसके लिए हम देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देते हैं। देश के प्रधान मंत्री जी द्वारा देश में अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं जिसमें प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक है और इस योजना के अन्तर्गत हर किसान-बागवान के खाते में प्रति वर्ष 6000/- रुपये डाले जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-01-2020 तक लगभग 597 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं और कुल 8,46,784 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस माननीय सदन में मैं कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में कांग्रेस के लोगों ने आम जनता को बहुत गुमराह किया और कहा कि मोदी जी ने जो 2000/- रुपये दिए हैं वे वापिस ले लिए जाऐंगे। इस प्रकार कांग्रेस के मित्रों ने झूठ की राजनीति करके लोगों को गुमराह किया। आज हमारे प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है और जल शक्ति विभाग की बात करें तो उसके लिए श्री मुकेश अग्निहोत्री जी बहुत उग्र हो रहे थे। हम माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं

कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 2,896/- करोड़ की कुल 327 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसके लिए हम केन्द्र की मोदी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 60 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि इस योजना में कुछ नहीं आया, मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें केवल अपनी जेब के लिए पैसा चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि इस योजना में मात्र 200 करोड़ रुपये आए हैं।

28-02-2020/1415/डी.सी.-एन.जी./2

मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि हमें किसी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए सारा पैसा आ ही जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कुल 7 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपये आ चुका है। मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 के बारे में बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है तो वह टोल-फ्री नम्बर 1100 पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में अधिकतर कांग्रेस के लोग शिकायत करते हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। कांग्रेस के मित्र जनमंच कार्यक्रम से बहुत परेशान हैं। जिस प्रकार जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हर माह किया जा रहा है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। जनमंच कार्यक्रम में जिला के सभी अधिकारी आते हैं और वहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जनमंच कार्यक्रम से पहले प्री-जनमंच का भी आयोजन किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारी वहां पर जाते हैं

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2020/1420/JK/HK/1

श्री किशोरी लालः-----जारी------

और मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में पांच कार्यक्रम हो चुके हैं, केवल मात्र पांच पंचायतें बची हैं और 560 लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। जब प्री-मंच में शिकायतें आती हैं और विभाग के अधिकारी खुद घर जा कर देखते हैं कि कहां पर नलका लगना है और कहां पर बिजली का मीटर लगना है, इससे हमारे कांग्रेस भाइयों को परेशानी होती है। प्री-मंच में पहले लोगों के सारे डॉक्युमैंट्स तैयार किए जाते हैं। चाहे किसी की रजिस्ट्री होनी है, इन्तकाल होना है और उसके अलावा जितने भी सरकारी दस्तावेज़ बनने हैं, वे वहीं पर सारे-के-सारे कागज़ात तैयार किए जाते हैं। प्रदेश सरकार नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करती है कि उज्जवला योजना के तहत आज लाखों लोगों को गैस के कनैक्शन दिए जाते हैं। हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जब गरीब लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं हो सका तब हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरूआत की गई जिसमें 2 लाख 76 हजार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हर घर को गैस का कनैक्शन फ्री दिया गया है, उसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज से 10-15 साल पहले जब गैस का कनैक्शन देते थे या तो वह ब्लैक में लेना पड़ता था या सब्सिडी में लेना पड़ता था लेकिन उसके बावजूद भी गैस कनैक्शन नहीं मिलते थे। हम आज प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जब गांवों के गरीब लोग जंगल में लकड़ी के लिए जाते थे और शाम को लकड़ी लेकर घर आते थे। जब घर में उन लकड़ियों को जलाते थे तो उस धूएं से उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। आज उससे निज़ात दिलाने के लिए सभी लोगों को गैस कनैक्शन दिए गए हैं। प्रदेश के युवा आर्थिक रूप से

कैसे स्वावलम्बी हों उस दृष्टि से हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। युवाओं को कैसे सुविधा दी जाए, उसके लिए 7 व 8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल

28.02.2020/1420/JK/HK/2

इन्वैस्टर मीट हुई थी, जिसका शुभारम्भ हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने किया था। किसानों, बागवानों, फूड प्रोसैसिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा हर एक क्षेत्र के लिए वहां पर इन्वैस्टर्ज़ आए और मैं उस मीट में स्वयं भी था। वहां पर लगभग 2,083 इन्वैस्टर्ज़ आए थे। कई इन्वैस्टर्ज़ तो दूसरे देशों से भी आए थे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं था और कहते हैं कि वहां पर घोटाला हुआ है। भाइयो और बहनों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस ढंग से वहां पर ग्लोबर इन्वैस्टर मीट हुई और उसका निमंत्रण आप लोगों को भी था लेकिन आप लोग उसमें नहीं आए। यदि आ जाते तो देखते कि वहां पर कितना अच्छा कार्यक्रम था। उसमें आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के 1 लाख 96 हजार युवाओं को नौकरी मिलने का प्रावधान है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का सपना है कि हमारा युवा वर्ग सैल्फ- स्टैंड हो, अपने आप वह अपना काम कर सकें, इसलिए मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की गई है जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 18 से 45 वर्ष की आयु के जितने भी युवा हैं, उनके लिए 50 लाख तक 25 प्रतिशत अनुदान की राशि दी जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए इस योजना का 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ी योजना लाई गई है और आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रधान मंत्री ने "आयुष्मान भारत योजना" का शुभारम्भ किया है। जब हम आज से पांच साल पहले आई.जी.एम.सी. में जाते थे तो गरीब लोगों की क्या हालत होती थी। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र से बहुत गरीब लोग इलाज करवाने के लिए यहां पर आते थे! उनको 15-15 दिन इलाज में लग जाते थे। हम भी उनकी कुछ-न-कुछ मदद करते थे और वे 15 दिन के बाद डॉक्टर से कहते थे कि हमें अब छुट्टी दे दो क्योंकि वे पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। देश के प्रधान मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि 5 लाख गरीब लोगों का इलाज फ्री में किया जाता है। यह गरीब लोगों के लिए हमारे देश व दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

28.02.2020/1425/SS-HK/1

श्री किशोरी लाल क्रमागत :

ताकि वे अपना इलाज मुफ्त में करवा सकें। मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री, आदरणीय जय राम ठाकुर जी और माननीय अध्यक्ष जो पूर्व में मंत्री रहे हैं का भी धन्यवाद करता हूं। जो लोग आयुष्मान भारत योजना में छूट गए थे उनको हिम केयर योजना के तहत लाया गया। उसमें सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक लोगों को इलाज के लिए दिये जा रहे हैं। मुझे पिछले कल एक फोन आया। एक बहुत ज्यादा बीमार थे और रामपुर हॉस्पिटल में थे। मैंने आज ही तुरन्त टेलीफोन किया और उसका हिम केयर योजना के तहत कार्ड बनवा दिया है। उस गरीब आदमी का वहां पर इलाज किया जायेगा। इसके लिए हम प्रदेश सरकार और आदरणीय जय राम ठाकुर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

आज हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारी सरकार में 1977 में आदरणीय शांता कुमार जी द्वारा शुरू की गई थी। जहां उस पेंशन में हमारी सरकार ने बढ़ोत्तरी की, वहां हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है और पेंशन के लिए जो 80 साल की आयु है उसे 10 वर्ष कम करके 70 वर्ष किया है। इसमें इन्कम का भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है और आज 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

आज यदि हम पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो मैं प्रदेश सरकार व आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले वर्ष पहली बार पर्यटन की दृष्टि से मेरे यहां बजट का प्रावधान किया। इसमें नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में भी बागा-सराहन में पहली बार बजट का प्रावधान किया है। इसके लिए जहां मैं वन मंत्री महोदय, श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं वहीं प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में मेरे चुनाव क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा। आज यहां पर रोज़गार की बात की है। विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के जो खाली पद पड़े हैं, हमारे विपक्ष के साथी, श्री राकेश सिंघा

जी पता नहीं कब का रिकॉर्ड लाए हैं, कब की यह पैंडेंसी है। पैंडेंसी थोड़ी है लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से रिकॉर्ड निकाला है उसमें जस्टिफिकेशन

28.02.2020/1425/SS-HK/2

नहीं है। ये कांग्रेस टाइम का कोई पुराना रिकॉर्ड ढूंढ करके लाए हैं। कांग्रेस के समय में जब स्कूल की बात आती थी तो जहां मिडल स्कूल चाहिए होता था वहां हाई स्कूल देते थे। जहां हाई स्कूल चाहिए होता था वहां कॉलेज देते थे और आज अगर मैं अपने आनी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो जिस ढंग से पिछली सरकार ने इतने स्कूल व कॉलेज खोल दिए हैं कि वहां स्टाफ नहीं है। आज मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस के समय में गलत स्कूल खोल दिए गए थे और कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं की थी, आज वहां पर स्कूल में स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में जहां तक पोस्टों की बात है 4278 पोस्टों का सृजन किया गया है। इसके अलावा हमारे इस प्रदेश में 15315 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। उसके अलावा विद्युत विभाग और एच0आर0टी0सी0 में 4 हजार से अधिक पदों को भरने का प्रावधान किया है। आज जिस ढंग से प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में हमारा एक सपना था, जिसके बारे में हमने बहुत सोचा था कि जलोड़ी जोत के नीचे टनल का निर्माण हो। उस टनल के निर्माण के लिए जहां हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं वहीं केन्द्र सरकार व आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करते हैं कि जलोड़ी जोत टनल के लिए जो डी0पी0आर0 बननी है उसके लिए हाल ही में पिछले महीने बाई एयर सर्वे हुआ है। यह हिन्दुस्तान के अंदर पहला सर्वे हुआ है। नॉर्वे की टीम आई थी। उसका टेंडर भी लग चुका है, साढ़े 5 करोड़ की उसकी डी0पी0आर0 बनी है। उसके साथ ही हमारा सैंज-ज्यूरी-ओट है जिसमें लैंड एक्वायर होनी है। वह 2020 की नोटिफिकेशन है। उसका भी टेंडर लग चुका है। उसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

पहले मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अंदर राशि 40 हजार रुपये मिलती थी, आज वह बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी है। इसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

28.02.2020/1430/केएस/वाईके/1

श्री किशोरी लाल जारी---

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने एक अलग से योजना "एक बूटा बेटी के नाम" से शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जब हम जन-समुदाय में नवजात कन्या के नाम पर पौधा रोपित करेंगे तो उस दृष्टि से वनों के महत्व के बारे में भी हम सभी को जानकारी मिलेगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। विपक्ष ने इसका विरोध किया, चलो, विपक्ष का एक रोल होता है, विपक्ष की भूमिका जरूरी होती है परन्तु विपक्ष के हमारे साथी बहुत ही ज्यादा झूठ बोल देते हैं। इस प्रदेश के विकास के लिए मैं मुख्य मंत्री जी व सभी मंत्रीगण का धन्यवाद करता हूं । जिस ढंग से हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर दोबारा से हिमाचल प्रदेश की सरकार बनेगी और विपक्ष के साथी बहुत कम संख्या में विपक्ष में ही रह जाएंगे। वर्ष 2022 में बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी सरकार रिपीट होगी और 50 प्लस का हमारा टारगेट होगा। ज्यादा न कहते हुए अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः धन्यवाद किशोरी लाल जी। आपने निर्धारित समय में सारी बात यहां पर रखी। अब माननीय सदस्य राम लाल ठाकुर जी चर्चा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले की आप चर्चा में हिस्सा लें, मैं सम्माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब हम अपना विषय रखते हैं तो इस माननीय सदन में भाइयों एवं बहनों शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो माननीय सदस्य और अगर मंत्री हैं तो मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए अपनी बात रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जो परम्पराएं हैं, उनका निर्वहन हमने करना है। यह कोई जनसभा नहीं है इसलिए कृपया इन बातों का ध्यान रखें। अब माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

28.02.2020/1430/केएस/वाईके/2

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी): अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में जो माननीय राज्यपाल महोदय ने 25 फरवरी, 2020 को अपना अभिभाषण दिया था, उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रश्न है, वह सरकारी दस्तावेज होता है। पहले केबिनैट में चर्चा होती है फिर चीफ सैक्रेटरी और हमारे दूसरे ऑफिसर्ज़ अभिभाषण बनाते हैं और उसके बाद राज्यपाल महोदय उसको विधान सभा के सामने रखते हैं। वही परिपाटी है, उसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय ने 25 तारीख़ को अपना अभिभाषण यहां पर दिया था। उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है, मैं यह कहना चाहूंगा कि चर्चा इस बात पर है क्योंकि साल भर में जो सरकार ने काम किया होता है या जब बजट सैशन में बजट पास होता है, बजट पास होने के बाद साल भर उसके ऊपर सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए, किस-किस मद में उनको कहां-कहां पूरा किया और उसके बाद वे अगले वर्ष के राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल होते हैं। पिछले वर्ष की कारगुज़ारी और अगले वर्ष में क्या होने वाला है, उसके लिए भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण संकेत करता है। यहां पर जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करुंगा कि उस तरफ से व्यवधान न हो लेकिन,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.2.2020/1435/av/yk/1

श्री राम लाल ठाकुर------जारी

मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यह सरकार बनी थी तो उससे पहले यहां पर माननीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। चुनाव के दौर के दौरान आप लोगों ने प्रदेश की जनता के बीच कहा था कि वीरभद्र सिंह की सरकार ने प्रदेश को कर्ज़ में डुबा दिया है। उस समय क्या, आज तो महेन्द्र सिंह ठाकुर जी भी एक

प्रश्न के जवाब में बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कर्ज़ 11,800/- करोड़ रुपये से 36,000/- करोड़ रुपये हो गया था। लेकिन आपने जो एक प्रश्न का उत्तर दिया है उसके अनुसार मैं यह कहना चाहूंगा कि आप भी दो साल में उस रिकॉर्ड को पार करने वाले हैं। आपने यहां पर एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आपकी सरकार ने 8821.85 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया है। ...(व्यवधान) जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा था इसलिए अब आप भी बीच में न बोलें। मैं किसी को भी बोलते समय नहीं टोकता और यही निवेदन मैं आपसे भी करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कर्ज़ लिया है इसमें तो केंद्र सरकार का भी कुछ कर्ज़ आया है। आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए जब आप वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा उठाए गए कर्ज़ की बात करते थे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो कर्ज़ ज्यादा ब्याज पर लिए गए थे उनको अदा करके मार्किट से कम ब्याज पर कर्ज़ लिए गए थे और वह भी प्रदेश के हक में थे। यह नहीं कि दो-तीन वर्षों का रिकॉर्ड उठाया और फिर कह दिया कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने इतने कर्ज़ ले लिए। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कर्ज़ के बिना काम भी नहीं चलता, कर्ज़ किस सरकार ने नहीं उठाया? मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप चर्चा करें कृपा करके ध्यान में यह बात भी रखें कि आज की तारीख में आप बिना कर्ज़ के नहीं चल सकते। लेकिन जब यह सरकार बनी थी तो आप अभिभाषण में केवल मात्र यह कह देते कि हम कर्ज़ नहीं लेंगे और इस प्रदेश को कर्ज़ मुक्त बनायेंगे। आपने उस दिशा में क्या कदम उठाये? कर्ज़ तो आप भी ले रहे हैं और चुनाव से पहले आपने यह प्रोपेगंडा किया था कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने कर्ज़ ज्यादा ले लिया, इस प्रदेश को बेच दिया और हम आयेंगे तो कर्ज़ नहीं लेंगे। मैं यह

28.2.2020/1435/av/yk/2

पूछना चाहूंगा कि क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसके बारे में एक शब्द भी लिखा गया है? हम जहां मुद्दों की बात करते हैं तो मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी शिमला एम0सी0 है। इस एम0सी0 में पहले की सरकार ने भी लोगों से वायदा किया

और कहा कि वन टाइम सेटलमैंट होगी। मगर लोगों के नक्शे आज की तारीख में भी फंसे हुए हैं। फिर आपकी सरकार सत्ता में आई और आपने भी कहा कि हम वन टाइम सेटलमैंट पॉलिसी लेकर आयेंगे। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसी बीमारी बन गई है कि आज हिमाचल प्रदेश में जहां-जहां पर भी होटल या मकान बन रहे हैं उनका जीना दूभर हो गया है। आपने भी कहा था कि हम इसके लिए वन टाइम सेटलमैंट पॉलिसी लेकर आयेंगे। आप इसके लिए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करवा लीजिए और एक डेट तय कर लीजिए कि जो ये मकान या होटल बने हैं क्या आप उनको उखाड़ देंगे। हमारा शिमला एक ऐसा स्थान है जहां पूरे प्रदेश के लोग बसे हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में तुरंत वीडियोग्राफी करके जहां-जहां पर भी

टी सी द्वारा जारी

28-02-2020/1440/TCV/AG-1

श्री राम लाल ठाकुर....जारी

शिमला के अंदर मकान बने हैं उसके बारे में कोई फैसला करें ताकि लोगों को जो पानी व बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, उसमें राहत मिल सकें। दिल्ली में पिछले चुनाव के दौरान केन्द्र सरकार ने 40 लाख रजिस्ट्रियां करवाई जिसके लिए वहां पर बड़े-बड़े होल्डिंग लगाये गये थे। मैं समझता हूं वे रजिस्ट्रियां नहीं थी, लोगों को लीज़ पर ज़मीन दी गई होगी और कहा गया होगा कि रजिस्ट्रियां हो गई हैं। दिल्ली के अंदर 40 लाख मकान बनाने के लिए ज़मीन दी गई, पंजाब के अंदर ग्रीन ट्रिब्यूनल की कोई प्रोब्लम नहीं है और ऐसा ही पंजाब सरकार भी कर रही है। मेरा माननीय मंत्री, ठाकुर महेन्द्र सिंह जी आपसे निवेदन है क्योंकि मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं है, वीडियोग्राफी करके one time settlement कर दी जाये ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की बिल्डिंग न बनायें और जिनकी बनी है, उनको वैध करार दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये बिल्डिंग्ज सरकारी जगह पर नहीं बनाई

गई हैं बल्कि ये सरकार के कुछ नियमों के अनुसार नहीं बनी है और अपनी जगह पर लोगों ने कुछ डैविएशन की है। आपने लोगों से वायदा किया था कि शिमला के लोगों को नई पॉलिसी लेकर आएंगे लेकिन इसमें उसका ज़िक्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत से साथियों ने धर्मशाला में हुई इन्वैस्टर्ज मीट का ज़िक्र किया। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें कितना पैसा खर्च हुए, कहां पर हुआ, किसने किया, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब धर्मशाला में इन्वैस्टर्ज मीट हुई और एम0ओ0यूज0 साइन हो गये तो सरकार को यह बताना चाहिए कि एम0ओ0यूज0 साइन होने के बाद कितने लोगों को रोज़गार मिला? कितनी इन्वेस्टमैंट हिमाचल प्रदेश में हुई और किस प्रकार से हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े और किस प्रकार से यहां औद्योगिकरण हुआ? अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्रियों का पलायन हुआ है। अभी पिछले दिनों मैं पांवटा साहिब गया था। सोलन

28-02-2020/1440/TCV/AG-2

जिला में 2 इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, मैं वहां भी गया था। मैंने वहां पर जानने का प्रयास किया कि वहां से कितने लोग काम छोड़कर चले गये हैं? मैं परवाणू की बात कर रहा हूं, वहां पर जो यूनिट्स लगे थे उनमें से लगभग 65 प्रतिशत यूनिट्स वहां से छोड़कर चले गये हैं। एक लेबर का काम करने वाला चाय बेच रहा था, हम उसकी दुकान में जाकर बैठ गये और पूछा कि आप कब से चाय बेच रहे हैं? उसने बताया कि मुझे यहां पर 35-36 साल हो गये हैं लेकिन अब मुझे नौकरी छोड़कर चाय बेचनी पड़ रही है। मैं गावं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। उसने बताया कि जो बड़े-बड़े यूनिट्स हैं, वे परवाणू से छोड़कर चले गये हैं। हमें पहले यह देखना चाहिए कि हिमाचल में जो यूनिट्स लगे थे, उनमें से कितने यूनिट्स अब यहां पर रह गये हैं? हम कह रहे हैं कि नई इन्वेस्टमैंट आयेगी और पर्यटन के ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन के लिए क्या हम बेसिक इंफ्रास्ट्रैक्चर तैयार कर पायें हैं? यहां पर हवाई जहाजों और हवाई पट्टियों

की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि कुल्लू में भुन्तर और मंडी व धर्मशाला का एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा लेकिन मैंने अख़बारों में फोटो देखें हैं, लोग वहां पर इसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कोई विरोध नहीं होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र की बात नहीं है। करीब 20 साल पहले डिफैंस के लोग आये थे, बिलासपुर में बनांस की धार है, वह घाघस के ऊपर की धारा है, यह बरमाणा तक है और इसमें कोई पेड़ नहीं है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-02-2020/1445/NS/AG/1

श्री राम लाल ठाकुर .....जारी

और इसमें लोगों की भी कोई ज़मीन नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर डिफैंस प्वाईंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा हवाई अड्डा बन सकता है तो वह बनांस की धार थी। आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मंडी वाले भी क्यों लड़ रहे हैं। मान लो आपको बिना लड़ाई के डिफैंस और स्वयं के लिए बड़ी हवाई पट्टी बनानी है तो आप बनांस की धार को छांट लो। वहां से आपकी ही पार्टी का विधायक है और आप उसको कहो तथा जा करके मौका देखो। वहां पर कोई पेड़ नहीं है और सरकारी ज़मीन है और बंजर पड़ी हुई है। आप वहां पर जितना मर्ज़ी बड़ा एयरपोर्ट बना लो लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। जहां पर लोग विरोध करते हैं आप वहां ध्यान देंगे। भाषण देंगे और फिर जब विरोध होता है तब पीछे जाकर बैठ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं टूरिज्म की बात करता हूं। जब तक हम इन कमियों को नहीं सुधारेंगे तब तक टूरिज्म ऊपर नहीं जा सकता है। आज की तारीख़ में आपकी कोई टूरिज्म की पॉलिसी नहीं है। यहां पर ईको-टूरिज्म की पॉलिसी शुरू हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं वन मंत्री था उस समय में माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे और ईको-टूरिज्म की पॉलिसी ले करके आए थे। यह हिमाचल प्रदेश के नौज़वानों के लिए थी। उसमें यह शर्त थी कि हम जंगल की ज़मीन के अच्छे-अच्छे प्वाईंट्स नौज़वानों को देंगे और उसमें बिल्डिंग बनाने वाला मैटीरियल रेत, बज़री आदि प्रयोग नहीं होगा बल्कि मिट्टी, गारा और पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद भी यहां पर वन मंत्री बने हैं। इस सारी पॉलिसी को स्क्रैप किया गया। ईको-टूरिज्म की छांटी हुई जगहें ऐसे लोगों को दे दीं जो अरबोंपति हैं। एक पुरानी बड़ी कंपनी है

जिसको आपने यह जगह दे दी जहां से जिला सोलन की सीमा शुरू होती है और वहां पर पांच सितारा होटल से भी ज्यादा कमाई हो रही है। फिर क्या ईको-टूरिज्म पॉलिसी हुई? हिमाचल प्रदेश के नौज़वानों को कोई रोज़गार नहीं मिला और न ही ईको-टूरिज्म पॉलिसी के मुताबिक उस मैटीरियल को प्रयोग कर पाए। टूरिज्म तभी विकसित होगा जब हम इन सारे विषयों की तरफ ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि 32-34 प्रतिशत लोग पन बिजली परियोजनाओं के लिए आए थे। हम सब जानते हैं कि पुरानी पन बिजली परियोजनाओं

28-02-2020/1445/NS/AG/2

का क्या हाल है? हमने बिजली उत्तर प्रदेश को बेची और उस समय वहां पर मायावती की सरकार थी। हमने दिल्ली को बिजली बेची वहां पर किसकी सरकार है सब जानते हैं। जो बिजली बेची उसका पैसा बहुत सालों बाद लिया गया। आज हमारे प्रदेश द्वारा पैदा की हुई बिजली की मार्केटिंग नहीं हो रही है। सोलर एनर्जी की वज़ह से हमें और ज्यादा धक्का लगा है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में छोटी-छोटी पन बिजली परियोजनाएं शुरू हुई हैं उनमें से कितनी पूरी हुईं, कितनी चली हैं और कितने लोग छोड़ कर चले गए हैं? मैं कहूंगा कि अंधेरे में छलांग लगाना ठीक बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव थे तो कौशल विकास भत्ते की बहुत चर्चा हुई थी। आप जब इस तरफ थे मैं उस समय यहां नहीं था तो उस समय आप लोग कौशल विकास भत्ते की बात करते थे और कहते थे कि कांग्रेस पार्टी और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बेकारी भत्ता देने की बात कही थी कौशल विकास भत्ते की बात नहीं की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि सरकार बताए कि आपने कौशल विकास भत्ते का विरोध किया था तो आपने इसको क्यों चला रखा है और कितने लोगों को आपने दो सालों में बेकारी भत्ता दिया है? आपने तो वायदा किया था कि कौशल विकास भत्ता होना चाहिए और नौज़वानों को रोज़गार देने के लिए कैश पेमैंट होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी कैश पेमैंट की है? इस अभिभाषण में कहा गया है 28.52 करोड़ रुपये कौशल विकास भत्ते पर खर्च हुए हैं। आज जब हम खनन माफिया

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

श्री राम लाल ठाकुर... जारी

वन माफिया या अन्य माफियों की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग चुनाव से पहले तो माफिया की बात करते थे, तो क्या आज हिमाचल प्रदेश में पहाड़ नहीं कट रहे हैं? क्या आज हिमाचल प्रदेश में जगंलों को बर्बाद नहीं किया जा रहा है? रोज अख़बारों में आ रहा है कि फलां-फलां जगह इतने लोग पकड़े गए हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में यह कहा गया था कि ये काम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि जब जांच हुई तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का महासचिव, वहां का एक वरिष्ठ नेता और उसका बड़ा भाई शामिल था। यह कोठीपुरा और चंगर एरिया बस्सी के केस थे। एक केस में तो जमानत ले ली गई और दूसरे केस को दबा दिया गया क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का महासचिव संलिप्त था। लेकिन आज कथनी और करनी में अंतर क्यों आ रहा है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे? मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो आप कह रहे हैं उस पर अमल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वालों को आप गले लगाओ और उनको बचाने का प्रयास करो। मैं ऐसे कई मामलों की लिस्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दूंगा जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है लेकिन कोर्ट में कोई चालान प्रस्तुत नहीं हुए हैं। इसका फायदा अपराधी को मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी जो नदियां बह रही हैं मैं उनके कटान की बात कर रहा हूं। जिला बिलासपुर में सीर, सुक्कर, सरयाली, घंबर, गमरोला और अली इत्यादि खड्डे बह रही हैं। ये खड्डे सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरिज हैं। यहां पर जब भी बात होती है तो स्वां नदी का ही ज़िक्र किया जाता है। इस नदी की चैनेलाइजेशन की बात भी मेरे समय में ही शुरू हुई थी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जिला बिलासपुर की किन-किन खड्डों को

चैनेलाइजेशन के लिए डाला है? आज अली खड्ड 15 फुट नीचे चली गई है और हमारे सिंचाई के क्यार 15 फुट ऊपर आ गए हैं। वहां पानी कहां से आएगा क्योंकि वहां पर दिन-रात मशीनों से रेत व पत्थर निकाले जा रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है? यह

28.02.2020/1450/RKS/AS-2

माफिया सिर्फ बोलने के लिए ही है? इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जंगलों को कटने से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने चिट्टे और नशे की बात की है। कई कह रहे हैं कि चिट्टा कांग्रेस के टाइम में चला। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि पहले चिट्टे का प्रचलन नहीं था। जब हम वर्ष 1978-85 में वकालत करते थे तो हमारे पास 61/01/14 में मामले आते थे। उन मामलों में चलती हुई भट्ठी (लाहण) पकड़ी जाती थी। इसके लिए मंझयारी गांव मसहूर था। इसके अलावा भांग, अफीम, सूलफे के केस भी पकड़े जाते थे, साधु बाबे पकड़े जाते थे। चिट्टे का प्रचलन पंजाब और जब अफगानीस्तान से पाकिस्तान वाला कोरिडोर खुला है तब से बढ़ा है। अब चिट्टे के बाद म्याऊं-म्याऊं भी आ गया। वह चाइना से आ रहा है। यहां लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए हमें पक्ष और विपक्ष को छोड़कर कोई नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री को भी इस संबध में पत्र प्रेषित किया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि हम इसे राजनीति परिधि में न लें। सभी बच्चे हमारे राष्ट की सम्पत्ति हैं और उन्हें इस लत से बचाना हमारा कर्त्तव्य है। अब कानून में यह संशोधन कर दिया कि यदि 2 ग्राम चिट्टा भी मिलता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। पिछले तीन महीनों में चिट्टे के विरुद्ध जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं उनमें 50 से ज्यादा लड़कियां चिट्टे के चक्कर में पकड़ी गई हैं। उनका क्या कसूर है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

श्री डी.टी. द्वारा... जारी

28.02.2020/1455/DT/AS-1

श्री राम लाल ठाकुरः जारी..... मैं निवेदन कर रहा हूं। उन बच्चो को अगर हम जेल में भेज रहे है। मान लो अगर किसी से 2 ग्राम भी पकडा गया तो उसे जेल में भेज दिया। इनमें अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे भी हैं। मॉ-बाप भी कुछ नहीं बोल सकते। रिश्तेदार भी कुछ नहीं बोल सकते। मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय कि सरकार कोई पॉलीसी लेकर आये जिसके अन्तर्गत कुछ सेन्टर खोलें जायें और उन सेन्टरों में बच्चों की नशे की आदत छुड़ा सकें। उन सेन्टरों में योग की शिक्षा दी जाये, वहां पर स्पोर्टस में बच्चों को डाला जाये ताकि जब बच्चा बाहर निकले तो वह सोचे की नहीं मैं तो नशा छोड़ने के लिए आया था। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को एक योजना लेकर आना पड़ेगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, चाहे वह पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, की सभी एक साथ इस बिमारी से निपटने का प्रयास करें। इस संदर्भ में हमारा एक उदेश्य होना चाहिए कि किसी का बच्चा बिगड़े न। इस लिए मैं कहूंगा की इसके ऊपर एक नई सोच से काम करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय जल शक्ति मन्त्री महोदय से अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। मैं, जल शकित मन्त्री महोदय, आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। कल आपने कहा कि मेरी नज़रें आपकी तरफ कुछ टेडी लग रही हैं। मेरी नज़रे हमेशा सीधी रहती हैं। राम लाल ठाकुर किसी को भी टेड़ी नज़र से नहीं देखता और न ऐसा हमने सीखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके नीचे जो अधिकारी हैं कृपा करके उन्हें पूछे की क्या कारण है? मेरे चुनाव क्षेत्र में 14.50 करोड़ रूपये का एक टेण्डर लगा दिया। जब मैंने आपके विभाग के अधिकारी को पूछा तो उसने कहा कि हम इसको स्पलिट नहीं कर सकते, हमें एक ही काम लगाने को बोला है और हमें ऐसा बोला है कि जो पुराने काम हैं उनको भी बन्द कर दो।

सदर चुनाव क्षेत्र में भी वही कम्पनी काम कर रही है। माननीय मन्त्री जी मेरा आपसे यह निवेदन है कि कृपा करके जो यह प्रक्रिया चली है, अधिकारियों ने पता नहीं क्या सोच कर यह कर दिया, आपके कान में भी डाल दिया होगा कि जनाब बड़ी अच्छी स्कीम है। अगर

आप सारे का सारा काम लुधियाना की कम्पनी को दे देंगे तो वह तो सारे कामों का सबलेट करेगा। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि कृपा करके यह जो 14.50 करोड़ का जो टेण्डर मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगा दिया, अब तो वह टेण्डर भी खुलने वाला है कृपा करके आप इसमें इण्टरवीन करें। ऐसा न हो की बाहर के लोग खायें और हमारे लोगों को खाने को रोटी भी यहां पर न मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय कहने को तो बहुत

28.02.2020/1455/DT/AS-2

कुछ था लेकिन समय की परिधि है इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। यह जो अभिभाषण है यह मात्र एक सरकारी दस्तावेज़ है। उस तरफ से आप कहेंगे की क्या बात है क्या बात है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बड़ा कुछ कर लिया। दुसरा पड़ाव महेन्द्र सिंह जी तक जाता है। फिर साथ में संसदीय कार्य मन्त्री तक। यह तो श्री जय राम ठाकुर जी ही जानते हैं। क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने। यहां से वहां जा रहें हैं, वहां से यहां आ रहे हैं। यह जो प्रक्रिया चली है मैं कहूंगा कि यह कोई सुखद प्रक्रिया नहीं है। मुख्य मन्त्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि यह जो परिस्थितयां आ रही हैं यह प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए ठीक संकेत नहीं दे रही है। आपने जो भाषण राज्यपाल महोदय के माध्यम से यहां पर रखा, मैं कहुंगा कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष- माननीय जल शक्ति मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय राम लाल ठाकुर जी ने अपने भाषण में बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आपने वन टाइम सैटलमैंट की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री परिषद ने कैबिनेट सब-कमेटी बनी है और हम कुछ ही दिनों के अंदर इसकी सारी फाइनल रिपोर्ट मंत्री परिषद में प्रस्तुत करेंगे। यह वन टाइम सैटलमैंट के लिए भी है और

श्री एन.जी. द्वारा जारी

28-02-2020/1500/डी.सी.-एन.जी./1

जल शक्ति मंत्री जारी.....

पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जो टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के अन्तर्गत लिए गए हैं उनमें से बहुत-से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वहां के लोग चाहते हैं कि हमें इससे बाहर किया जाए। आपने एक टैण्डर की बात कही है, मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के टैण्डर के लिए हमने दो श्रेणियां बनाई हुई हैं। ऐसी योजनाएं जिनकी लागत 15 करोड़ रुपये से कम हैं उनके लिए सभी प्रकार के मैटेरियल कॉम्पोनेंट को जल शक्ति विभाग देगा और उसके लेबर कॉम्पोनेंट टैण्डर हिमाचल प्रदेश के petty contractors को दिया जाएगा। आप जिस टैण्डर की बात कर रहे हैं यदि वह 15 करोड़ से कम का होगा तो मैं उसके बारे में पता करूंगा और हमने जो मापदण्ड रखें हैं वे Pick & Choose करने के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक समान हैं। जहां-जहां 15 करोड़ से कम के टैण्डर होंगे वहां पर लोकल लोगों को टैण्डर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह सभी कार्य समयबद्ध किए गए हैं, इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि आज काम ले लिया और 4 माह बाद काम शुरू किया जाए। हमने लक्ष्य तय किया है कि जल जीवन मिशन को दिनांक 31-08-2022 तक पूर्ण करना है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर चला हुआ है। माननीय श्री राल लाल ठाकुर जी इस विषय पर जो Best possible होगा मैं वह अवश्य करूंगा।

28-02-2020/1500/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्षः धन्यवाद ठाकुर साहब। अब माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप जी इस चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप (पच्छाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। जिस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस देश व प्रदेश के लिए विकास कार्य किए

हैं वे सभी अपने आप में बेहतरीन साबित हुए हैं। जन सेवा और सुशासन हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और हमारी सरकार का ध्येय है। हमारी सरकार ने हर वर्ग की चिन्ता करते हुए अनेक योजनाएं तैयार की हैं और इन योजनाओं से कोई भी वर्ग अछुता नहीं है। महिला वर्ग, अनुसुचित जाति वर्ग, युवा वर्ग व अन्य सभी वर्गों को अनेक योजनाओं में शामिल किया गया है और ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिन्होंने ने इन योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं उठाया हो। योजनाओं की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पैंशन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्य मन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्य मन्त्री स्वावलम्बन योजना, जनमंच, मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100, शक्ति बटन ऐप, गुड़िया हेल्पलाईन-1515, होशियार सिंह हेल्पलाईन-1090, ग्लोबल इनवेस्टर मीट, हिम प्रगति पोर्टल, नशे का रोकथाम अभियान, सहारा योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना, नई राहें नई मंजिलें योजना इत्यादि को लागू किया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार की सभी उपलब्धियां हमारे समक्ष हैं और जिन्हें इस दस्तावेज़ में अंकित भी किया गया है। यह सब माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, 2 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई भी विभाग और कोई भी वर्ग नहीं है जहां विकास कार्य और जनहित की सेवा नहीं पहुंची हो।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2020/1505/JK/HK/1

श्रीमती रीना कश्यपः------जारी------

सब का विकास, सब का साथ, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का इस प्रदेश की सेवा का मूल मंत्र रहा है और जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगी तो इस योजना के अन्तर्गत 54 करोड़ 26 लाख

रूपए की राशि हमारे पच्छाद के लिए स्वीकृत हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी का पच्छाद की जनता की ओर से धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा जनमंच और माननीय मुख्य मंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने जनमंच के माध्यम से एक ऐसी योजना लाँच की है जिसके माध्यम से स्थानीय स्तरों पर लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है। जनमंच एक ऐसा माध्यम है जिसमें बिना भय के हर व्यक्ति अपनी बात सरकार और प्रशासन के सामने रख सकता है। सच्चे शब्दों में यही एक असली लोकतंत्र है। माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इस कार्यक्रम के तहत 16 फरवरी, 2020 तक 189 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 45 हजार 708 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई हैं। इनमें 41 हजार 698 शिकायतों एवं मांगों का निपटारा किया गया है और कुल शिकायतों का लगभग 91 प्रतिशत है, जिसका निपटारा कर दिया गया है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

इसके अलावा मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि महिलाओं का इन्होंने दुख-दर्द समझा है। "महिला गृहिणी सुविधा योजना" के तहत प्रदेश में कुल 2 लाख 76 हजार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 01,75, 514 घरेलू गैस कनैक्शन आबंटित किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब प्रदेश में ऐसा कोई भी पात्र परिवार घरेलू गैस कनैक्शन से वंचित नहीं है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में इस उद्देश्य में सर्वप्रथम रहा है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निवेश आमंत्रित करने तथा युवाओं को

28.02.2020/1505/JK/HK/2

रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए कांगड़ा जिला के धर्मशाला में ग्लोबल इन्वैस्टर्ज मीट का आयोजन किया। इस मीट के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने 1 लाख 96 हजार व्यक्तियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ 97 हजार 700 करोड़

रूपये के निवेश हेतु 736 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारा हिमाचल ऊंचाई के शिखर तक पहुंचेगा। यह हमारा उद्देश्य है और यह हमारी सरकार का चहुंमुखी विकास का उद्देश्य है। ग्लोबल इन्वैस्टर्ज़ मीट एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए है। इसके अलावा मैं पर्यटन की दृष्टि से बात करूंगी तो एक नई योजना है "नई राहें, नई मंजिलें" उसके अन्तर्गत मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगी तो इसके अन्तर्गत सैरजगास पंचायत और करगाणु पंचायत के लिए साढ़े 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। मैं पच्छाद की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा राजगढ़ उप-मण्डल के रासुमांदर क्षेत्र में आई.टी.आई. खोलने की कैबिनैट मंजूरी दी है। इसको खोलने की जो मंजूरी दी है, उससे रासुमांदर में एक खुशी की लहर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर रोज़ एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

28.02.2020/1510/SS-YK/1

श्रीमती रीना कश्यप क्रमागत :

जोकि हमारे प्रदेश के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है।

इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न बोलते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं और जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका भरपूर समर्थन करती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

28.02.2020/1510/SS-YK/2

अध्यक्ष : धन्यवाद, रीना कश्यप जी। अब चर्चा में माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी भाग लेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़)ः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहां पर हमारे मित्र साथी बैठे हैं, यहां पर बहुत लम्बी-लम्बी बातें कही गईं। कुछ बातों का श्रेय लेने का प्रयास सत्तापक्ष की तरफ से किया गया। सबसे पहले यहां पर राम जन्म भूमि पर राम मंदिर निर्माण की बात कही गई। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें बहुत लम्बे समय से विवाद था जिसको अब सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया है। हम इसका स्वागत करते हैं यह एक ऐतिहासिक फैसला है।

दूसरे, यहां पर धारा-370 की बात कही गई। ठीक है, आपकी केन्द्र में सरकार है, वहां पर आपकी मैजोरिटी है। राज्यसभा में भी आपकी मैजोरिटी है। इसलिए आप इससे भी आगे बहुत फैसले कर सकते हैं। लेकिन यह फैसला करने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसको काबू करना केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है। देश टूटे न, देश बचा रहे और देश इकट्ठा रहे, इसकी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार पर निर्भर करती है। यहां पर कई योजनाओं का ज़िक्र किया गया। केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'जल जीवन मिशन', जिसमें 2896 करोड़ रुपये की 327 योजनाओं की स्वीकृति की बात यहां पर रखी गई है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि सिंचाई से संबंधित जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं हमारे भी निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में कुछ चैकडैम बन रहे हैं लेकिन जो उनकी क्वालिटी या काम करने का तरीका है वह सही नहीं है। वैसे मैंने आपके पास जाना था और आपके ध्यान में बात लानी थी, शायद वह बात आपके ध्यान में न हो। वहां पर जो चैकडैम बनने हैं उनकी फाउंडेशन 2-2 फुट तैयार की जा रही है जोकि बड़ी चिन्ता का विषय है। कल को वे चैकडैम टूट सकते हैं, भारी नुकसान हो सकता है। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

जो आपकी प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि है, यहां पर कहा गया कि 846784 किसानों को 21 जनवरी, 2020 तक 597 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। लेकिन हमने बहुत से किसान ऐसे देखे हैं जिनको अभी भी उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ या उनको जानकारी नहीं है या जान-बूझकर प्रशासन उनको इस योजना का लाभ नहीं देना चाहता। अगर सचमुच में हमने इस योजना को सफल कराना है तो इसकी मोनिटरिंग और चैकिंग बहुत आवश्यक है।

28.02.2020/1510/SS-YK/3

दूसरा यहां पर कहा गया कि सेवा और सुशासन मेरी सरकार का संकल्प है और इसके अंतर्गत जो योजनाएं शुरू की गई हैं चाहे वह मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना है या नई राहें नई मंजिलें योजना, सहारा योजना, 1100 हैल्प लाइन, गुड़िया हैल्प लाइन, होशियार सिंह हैल्प लाइन है। इसमें अनेक प्रकार की योजनाओं का ज़िक्र किया गया है। सरकार ने प्रदेश में कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 8 नवम्बर, 2019 को निवेश आमंत्रित करने के लिए ग्लोबल इन्वैस्टर मीट का आयोजन किया था। हमारे देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने इसका शुभारम्भ किया था। लेकिन जिस ढंग से वहां पर उद्योगपति आने चाहिए थे उतनी संख्या में नहीं आए।

जारी श्रीमती के0एस0

28.02.2020/1515/केएस/वाईके/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा जारी---

मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं तो केवल सुझाव देना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे जो पहले उद्योग स्थापित हुए हैं, वे चाहे नाहन में हैं या सोलन जिला के बद्दी-बरोटीवाला में हैं, जिस ढंग से वहां पर उद्योगपतियों को सहूलियतें मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही हैं। जो वातावरण उनके अनुकूल होना चाहिए, वह नहीं है। वहां पर रोड़ की, यातायात की स्थिति बहुत ही ख़राब है। प्रदूषण बहुत है । जो उद्योग हमारे पहले वहां पर स्थापित हुए हैं, अगर वहां पर उनको हम अच्छे ढंग से ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश व देश में अच्छा माहौल बनेगा और निवेशक खुद निवेश करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आएंगे। इसी तरह हमारे वहां पर बी.बी.एन.डी.ए. बना हुआ है। यहां पर श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, ये हमारे पुराने साथी हैं और मैंने इनको कहा था कि बी.बी.एन.डी.ए. का 70-80 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है। इसमें विधायकों की कोई भूमिका नहीं है। परमजीत सिंह पम्मी भी वहां से विधायक हैं और मैं भी नालागढ़ से विधायक हूं। जो पैसा है उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। हमने देखा है, हम भी जाते हैं और पंचायतों के प्रधान भी

वहां पैसे लेने जाते हैं और एक दरख्वास्त के ऊपर 10-10 लाख रुपये सेंक्शन हो जाते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस पैसे का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। यह पैसा वहां खर्च होना चाहिए जहां पर हमारे उद्योग लगे हैं ताकि उनकी सड़कें ठीक हों, उनके पार्क ठीक हों और उनके आने-जाने के लिए वहां पर हम अच्छा माहौल स्थापित कर सके। आप जानते हैं कि पंचायतों के पास तो और भी बहुत बजट होता है , मनरेगा के तहत करोड़ों रुपये खच किए जा सकते हैं । उस पैसे को अच्छे ढंग से इकट्ठा करके जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी डवल्पमैंट में उसको लगाया जाना चाहिए ताकि बाहर के उद्योगपति भी वहां पर आकर्षित हों।

अध्यक्ष महोदय, "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" के माध्यम से किसानों को सोलर ऊर्जा चलित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत, व 3 से अधिक किसानों को समूह आधारित बाड़बंदी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे

28.02.2020/1515/केएस/वाईके/2

नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में क्योंकि बंदरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है, नील गाय, बारह सींघा व जंगली सूअर वहां पर आते हैं और किसानों ने बहुत सालों से आवेदन कर रखा है लेकिन उनको अभी भी सोलर ऊर्जा चलित बाड़ प्राप्त नहीं हो सकी है। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है।

सरकार ने हर घर को नल उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता दर्शायी है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा "जल जीवन मिशन योजना" की शुरूआत की है लेकिन विभाग हर घर को नलका उपलब्ध करवाने में नाकाम रहा है। जब गरीब लोग एक्सिअन, आई.पी.एच. के पास जाते हैं, जो बेचारे पाइप नहीं खरीद सकते और जो अपने प्लास्टिक के पाइपों को चेंज करना चाहते हैं, विभाग के अधिकारी उनको इस योजना की जानकारी नहीं देते ओर न ही उनको इस योजना का लाभ देने का प्रयास करते हैं। वे लोगों

से कहते हैं कि अपने पाइप खरीद कर लाओ, ऐस्टिमेट बनाकर गरीब लोगों को दे देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, "मुख्य मंत्री रोशनी योजना" गरीब परिवारों को विद्युत कनैक्शन देने के लिए शुरू की गई है लेकिन एक्सिअन जो एच.पी.एस.ई.बी. के हैं, डिविज़न में हमने देखा, इस योजना के पात्र बहुत से लोग हमारे पास आते हैं लेकिन उनके भी ऐस्टिमेट बनाए जाते हैं। उनको कोई अधिकारी नहीं समझाता कि आप इस काम को फ्री करवा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ तभी हो सकता है यदि इन पर चैक रखा जाए।

यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई, मैं आपको नालागढ़ हॉस्पिटल की बात बताना चाहता हूं। 16 दिसम्बर, 2002 को जब प्रदेश में प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, जगत प्रकाश नड्डा जी नालागढ़ आए। वहां हमारा जो हॉस्पिटल है उसके 100 बैड के ब्लॉक का उन्होंने उद्घाटन किया। उस वक्त नालागढ़ में डॉक्टरों की संख्या 18 थी लेकिन अब वह 10 के करीब रह गई है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.2.2020/1520/av/yk/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा------जारी

नालागढ़ एक इण्डस्ट्रियल एरिया है और वहां पर दूसरे राज्यों के बहुत से प्रवासी बसे हुए हैं। स्थानीय जनता और प्रवासियों की संख्या को देखते हुए वहां पर डॉक्टर्ज की संख्या बहुत कम है तथा प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहां अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अनेस्थेसिया का डॉक्टर भी नहीं है तथा डायलिसिस की सुविधा भी नहीं है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने वहां पर जो सौ बैडिड हॉस्पिटल दिया है उसको देखते हुए वहां पर कम-से-कम उस हिसाब से स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए। इसी तरह से कृषि और उद्यान विभाग की

बात करना चाहता हूं। हमारे वहां पर ट्रेक्टर और ट्यूब वैल सिंचाई के लिए मिलते हैं। लेकिन उसमें भी सब्सिडी अमीर लोगों को मिलती है और गरीब व्यक्ति रह जाता है इसलिए इस बारे में भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश का गरीब आदमी तो इसका लाभ नहीं ले पा रहा जिसका इस पर वास्तव में अधिकार होना चाहिए। यहां पर नशा निवारण के बारे में भी बातें कही गईं। हमारी प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीमा से लगते दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे नशे को रोका जा सके। लेकिन हमारे बी0बी0एन0डी0ए0 में नशा सरेआम बिक रहा है। वहां पर चिट्टा, अफीम, भुक्की, चरस, गांजा इत्यादि नशे की चीजें आम बिक रही हैं और इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। यहां पर मैं नशा निवारण हेतु खोले गये केंद्रों की बात भी करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले न्यू नालागढ़ में राजपुरा के एक युवक को नशा छुड़ाने के लिए ले गए मगर वहां उसकी किस स्थिति में मृत्यु हुई यह किसी को पता नहीं और यह बड़े दुःख की बात है। लोगों ने जो अपने आप नशा निवारण केंद्र खोले हैं इस बारे में जांच होनी चाहिए कि उनको किसने लाइसेंस दिए हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के बारे में भी बड़ी-बड़ी बातें कही गईं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो लम्बरदार होते हैं उनका गांव में एक प्रमुख स्थान होता है। मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि उनकी भी कुछ मांगे ज़ायज़ होती है। मैं यह कहना

28.2.2020/1520/av/yk/2

चाहता हूं कि लम्बरदारों को राजस्व कार्यों में भी शिनाख्त करने का अधिकार होना चाहिए। कई बार प्रधान या बाहर से कोई वकील कर देता है जबकि उनको वास्तविकता का पता नहीं होता। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लम्बरदारों को पंचायतों का स्थाई सदस्य बनाया जाना चाहिए। लम्बरदार को गांव की पूरी जानकारी होती है इसलिए जो लोग नशा करते हैं उसके लिए भी लम्बरदारों को पावर मिलनी चाहिए कि उन लोगों को ढूंढे और जांच करे कि कौन लोग नशा करते हैं। उनको यह अधिकार होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध लम्बरदार कार्रवाई कर सके। इसके साथ मैं यह

मांग भी करना चाहता हूं कि सरकार लम्बरदारों को फ्री बस यात्रा सुविधा प्रदान करे। यहां पर सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों का भी ज़िक्र है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे होम गार्ड भाई दिन-रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनकी नौकरी पूरी हो जाती है तो वे बिना पेंशन के घर चले जाते हैं। हमारे होम गार्ड भाइयों की ड्यूटी भी कंटीन्यू होनी चाहिए। उनकी नौकरी में ब्रेक नहीं होनी चाहिए और उनके लिए कोई स्थाई नीति बननी चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी इस बारे में आदेश है। हमारे बी0बी0एन0डी0ए0 में होम गार्ड के 60 पद थे मगर बी0बी0एन0डी0ए0 एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण और वहां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पद दोबारा सृजित किए जाने चाहिए ताकि वहां की कानून-व्यवस्था अच्छे ढंग से चल सके। इसी तरह से मैं किसानों की बात करना चाहता हूं कि कई जगह चकोता लगा होता है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 चकोताधारक हैं तथा उसमें से करीब 10,000 तो हमारे नालागढ़ से ही होंगे। उनकी मांग भी ज़ायज़ है और वे अपनी मांग को लेकर कई बार मुख्य मंत्री जी से भी मिले हैं। हमारे बड़े किसानों में ये चकोताधारक भी शामिल हैं। प्रथम चरण में जो 5 बीघा भूमि चकोताधारक को दी है उस भूमि का पूर्ण रूप से उन लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

28-02-2020/1525/TCV/AG-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा....जारी

उनको ज़मीन दे दी गई है, लेकिन उनको खैर के पेड़ों को काटने का कोई हक नहीं है। उन पेड़ों की परवरिश इन लोगों ने की है। इन चकोताधाकों के पास जो ज़मीन है, पहले सरकार इनसे 50 पैसे प्रति बीघा लेती थी लेकिन अब सरकार ने 1000/- रुपये प्रति बीघा कर दिया है। हम चाहता हूं कि इसको 100/- रुपये प्रति बीघा किया जाना चाहिए। वर्ष 1956 से 1992 तक जिन किसानों को ज़मीनें पट्टानामा, नौतोड़ या चकोते पर पंचायत या सरकार ने दी है, उन्हें इस भूमि का पूर्ण रूप से मालिक बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से

नालागढ़ में एक चंगर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर सी0एच0सी0 हॉस्पिटल खुलना चाहिए क्योंकि लोगों को इलाज़ करवाने के लिए 20-25 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में पी0एच0सी0, जोघों हैं और वहां पर 7-8 बीघा ज़मीन है, उसको सी0एच0सी0 का दर्ज़ा मिलना चाहिए। इसी तरह से नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में बहुत जगह में डिग्री कॉलेज हैं लेकिन चंगर क्षेत्र जोकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पर डिग्री कॉलेज खुलना अति-आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत, कश्मीरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोघों पड़ता है और वहां पर 20 बीघा ज़मीन उपलब्ध हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको वहां पर खोला जाये।

दूसरा, नालागढ़ को जिला का दर्ज़ा मिलना बड़ा जरूरी है। वहां पर पुलिस का हैडक्वार्टर खुला हुआ है और एक्साइज़ का ए0टी0सी0 वहां पर बैठता है। इसके अलावा ड्रग्ज़ कंट्रोलर व बी.बी.एन.डी.ए. का सी0ओ0 वहां पर बैठता है। यदि नालागढ़ को जिला बना दिया जाये तो इससे वहां लोगों को सुविधा होगी। नालागढ़ और दून क्षेत्र के किसानों के लिए स्वॉयल टैस्टिंग लैब उपलब्ध नहीं है। उन्हें मिट्टी टैस्ट करवाने के लिए सोलन जाना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नालागढ़ में स्वॉयल टैस्टिंग लैब खोली जाये। जो शहीद स्मारक या शहीद यादगार गेट बनाये जाते हैं, हम उनको 'विधायक निधि' और 'सांसद' निधि से पैसा नहीं बना सकते हैं। इसलिए गेट बनाने के लिए उनको पैसा दिया जाना चाहिए।

28-02-2020/1525/TCV/AG-2

अध्यक्षः माननीय विधायक महोदय, वाइंड अप करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। बी0बी0एन0डी0ए0 के लिए जो पैसा डवलपमैंट के लिए दिया जाता है, उसमें वहां के स्थानीय विधायक की भूमिका भी होनी चाहिए। एक बड़ी विचित्र बात है कि वहां पर जो सड़कें बन रही है, उसमें कंकरीट सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। जिन लोगों के घर वहां पर है और वहां के जो

स्थायी निवासी हैं, वे ठेकेदारी कर रहे हैं। जब उसकी चैकिंग और टैस्टिंग वही लोग कर रहे हैं तो काम ठीक कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर जो लोकल आदमी लगाये हुए हैं उनको वहां से हटाकर नालागढ़ में कहीं और जगह लगाया जाये और उनको ऐसा महत्वपूर्ण पद न दिया जाये। नालागढ़ में पी0एच0सी0, नंड है, उसके लिए 45 लाख रुपये सरकार से आ गये हैं लेकिन अभी तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके लिए और पैसा देकर उसके टेंडर किए जाएं। डिग्री कॉलेज, राम शहर के लिए 85,00000/- लाख रुपया आया है और उसका 12 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बना है। वहां विद्यार्थी अभी भी बाहर बैठ रहे हैं। इसके लिए भी अढ़ाई करोड़ रुपया और देकर इसका काम शुरू किया जाये। सब-तहसील पंजैरा के लिए भी 50,00000/ लाख रुपया आया है। इसके लिए और पैसों की जरूरत है। इसको और धनराशि उपलब्ध करवाई जाये ताकि इसकी बिल्डिंग का काम हो सकें। तहसील राम शहर के लिए भी 50,00000/- रुपये आये हैं लेकिन लोक निर्माण विभाग इसके टेंडर नहीं कर रहा है। इसी तरह से 'मुख्य मंत्री निःशुल्क दवाई योजना', 'जनमंच', 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' और कई योजनाओं का यहां पर ज़िक्र किया गया।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-02-2020/1530/NS/AG/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा.....जारी

"मुख्य मंत्री खेल विकास योजना" के तहत मैंने अपनी प्रायोरिटी गवर्नमैंट सीनियर सेकैंडरी स्कूल, जोगों के लिए दो साल पहले दी थी और इसके लिए लगभग 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में 26 राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया है। 25 राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाया गया है। राजकीय उच्च विद्यालय, साई चढ़ोग, राजकीय उच्च विद्यालय, मलैहणी और

राजकीय उच्च विद्यालय, गुनाह के लिए सरकार से मांग करता हूं कि इन स्कूलों को अपग्रेड करके 10+2 किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सलैहडां और राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बंकोटा को मिडल स्कूल का दर्ज़ा देना अति आवश्यक है क्योंकि राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सलैहडां में शत-प्रतिशत विद्यार्थी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि प्राईवेट स्कूलों की फ़ीस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। प्राईवेट स्कूल वाले मनमानी फ़ीस लेते हैं। किसानों और गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बिजली बनती है और यहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। सभी किसानों के लिए जैसे दिल्ली और पंजाब सरकार ने बिजली व पानी का मुफ्त किया है तो मेरी सरकार से मांग है कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28-02-2020/1530/NS/AG/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जिया लाल जी भाग लेंगे।

श्री जिया लाल (भरमौर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको इस गरिमामय पद पर आसीन होने के लिए बधाई देना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण 25 फरवरी, 2020 को दिया गया और इसका प्रस्ताव आदरणीय बलबीर जी ने किया तथा इसका समर्थन आदरणीय राकेश जम्वाल जी ने किया है। मैं इस चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। "दो साल विश्वास के, प्रगति और विकास के।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने दो वर्ष पूर्व सत्ता संभाली और हिमाचल प्रदेश में विकास की नई-नई गाथाएं लिखीं हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कई अवार्ड मिले हैं। इसके लिए मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुझसे पहले भी कई वक्ताओं ने यह बात कही है। "जल जीवन मिशन" योजना के अंतर्गत 2896 करोड़ रुपये की 327 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और माननीय जय राम ठाकुर जी व माननीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूं। "प्रधान

मंत्री किसान सम्मान निधि" के तहत 21 जनवरी, 2020 तक लगभग 597 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। जिससे लगभग 8,46,784 किसान लाभान्वित हुए हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में जनहित कार्य योजनाएं शुरू की हैं और उनमें से एक "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" है। अध्यक्ष महोदय, यह पेंशन पहले भी दी जाती थी। जब पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने भी इस पेंशन की राशि दोगुणी की थी कि जो व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाएगा उसको डबल पेंशन मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, वैसे कांग्रेस वाले बहुत टैक्निकल लोग हैं। ये जानते थे कि 80 साल तक कोई बचेगा ही नहीं अगर कोई बच भी गया तो वह पेंशन नहीं मांगेगा। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने इसकी आयु सीमा घटा कर 80 से 70 वर्ष कर दी। इसके लिए मैं माननीय जय राम ठाकुर जी का व माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.02.2020/1535/RKS/AG-1

श्री जिया लाल... जारी

'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना', मैं जनजातीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घरों के लिए कभी गैस कनैक्शन मिलेंगे। अगर हम साच-पास से जाएं तो वहां से पांगी घाटी लगभग 300 किलोमीटर दूर है और जम्मू-कश्मीर की ओर से जाएं तो इसकी दूरी लगभग 750 किलोमीटर पड़ती है। उस दुर्गम घाटी में हमारी सरकार ने 'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' के तहत गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ...(व्यवधान)

जब जनमंच की बात आती है तो कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी होती है। जिन कांग्रेस पार्टी के लोगों के काम सरकार के पास जाकर नहीं होते, वे जनमंच में अपने काम करवा लेते हैं। जनमंच में अधिकारियों को तुरंत काम करने पड़ते हैं चाहे वे किसी भी दल के लोग क्यों न हों।

'मुख्य मंत्री हैल्प लाइन योजना।' अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक कांग्रेस समर्थक व्यक्ति था। पूर्व सरकार के समय से उसके घर में नलका नहीं लग रहा था। जब 'मुख्य मंत्री हैल्प लाइन योजना' में इसकी शिकायत की गई तो दूसरे दिन ही उसके घर में नलका लग गया। वह मेरे घर पहुंचा और कहने लगा कि आपकी सरकार बहुत अच्छी है और मैंने अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है। ...(व्यवधान)

आज गुड़िया हैल्प लाइन, होशियार सिंह हैल्प लाइन और ऐसी कई योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया आप चेयर को अड्रैस करें।

श्री जिया लालः अध्यक्ष महोदय, मैं जल जीवन मिशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कल जब माननीय मुकेश जी चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि इसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की

28.02.2020/1535/RKS/AG-2

सरकार है और बजट का प्रावधान सरकार करती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10,92,26,000/- रुपये की योजना स्वीकृत हुई है जिसमें अब काम भी शुरू हो गया है। लोगों के घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब वहां जल भी है और नल भी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय जल शक्ति मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

नाबार्ड में 4,07,38,000/- रुपये, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. में 11,30,01,000/- रुपये, एस.सी.एस.पी. में 2,42,02,000/- रुपये, डी.ए.एस.पी. में 02,61,63,000/- रुपये, टी.ए.एस.पी. में 11,80,74,000/- रुपये स्वीकृत हुए हैं और ये सभी आंकड़े मेरे जनजातीय क्षेत्र के हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 6 किलामीटर सड़क का निर्माण हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो दो वर्ष के कार्यकाल में ही 37 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गई है और वहां पर बसें चलना शुरू हो गई हैं। 41 किलोमीटर सड़कों में टारिंग की जा चुकी है। पुल के निर्माण के लिए 10,07,13,000/- रुपये, सड़कों के निर्माण के लिए 01,79,54,70,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा संस्थानों के लिए 22,86,50,000/- रुपये, स्वास्थ्य के लिए 02,12,53,000/- रुपये, पुलिस भवन के लिए 70,65,000/- रुपये, आर्ट एंड कल्चर में 01,65,01,000/- रुपये, पशुपालन विभाग में 36,86,000/- रुपये, गृह रक्षक में 24 करोड़ 58 हजार का प्रावधान है।

श्री डी.टी. द्वारा... जारी

28.02.2020/1540/DT/-1

श्री जिया लाल.. जारी

कुल मिलाकर 217 करोड़ 58 लाख 4 हजार हमारे जनजातीय क्षेत्र में खर्च हो रहे हैं। ट्राइबल एरिया सब प्लान में प्रदेश सरकार राज्य योजना की 9 प्रतिशत राशि जनजातीय उप योजना के लिए चिन्हित कर रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में जनजातीय उप योजना के अंतर्गत 639 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 20 करोड़ 60 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद-275 -ए के अंतगर्त राज्य सरकार को मिलने वाली सहायता अनुदान के अंतगर्त वर्ष 2019-20 में 5,314 करोड रुपये प्राप्त हुए। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही प्रदेश के लिए एक साथ तीन एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोलने की स्वीकृती भारत सरकार से प्राप्त हुई है तथा यह विद्यालय भरमौर, पांगी व लाहौल में शैक्षिणिक सत्र वर्ष 2019-20 में आरंभ कर दिए गए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के निर्माण के लिए अब तक 33.36 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं।

इन विद्यालयों के लिए भूमि का चयन भी कर दिया है तथा भूमि हस्तांतरण की प्रकिया भी आरंभ कर दी गई है। भरमौर व पांगी के लिए मैं धन्यवाद करनाचाहूंगा केंद्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का व आदरणीय जय राम ठाकुर जी का विशेषकर माननीय अध्यक्ष जी आपका भी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में टेलि मैडिसिन सेवा भरमौर, पांगी व लाहौल तीनों जगह काम कर रही है। सर्दियों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा हैलीकोप्टर सेवा प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान हैलीकोप्टर सेवा के लिए अनुदान हेतु मामला भारत सरकार से उठाया गया है जिसके फलस्वरूप जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से पहली बार 4 करोड़ रुपये अनुदान राशि के रूप में प्रापत किए गए। इस वर्ष के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। भरमौर में 01,957 करोड़ की लागत से सिविल अस्पताल जिसका कई वर्षों से काम लटका हुआ था का शिलान्यास आदरणीय मुख्य मंत्री जी करके आए थे उसके लिए धन का प्रावधान कर दिया गया है और काम भी युद्ध स्तर में हो रहा है। इसके साथ पांगी घाटी में 5 करोड़ 62 लाख की लागत से आई.टी.आई. भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले जो स्कूलों के बारे में चर्चा की गई है कि वहां पर अध्यापकों की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्कूल हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। इनके नाम है सकरैणा और जुंआ। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी

28.02.2020/1540/DT/-2

और जब ये जाने वाले थे तो उस समय के मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से जब कोई प्राइमरी स्कूल खोलने की बात करता था तो वह कहते थे कि आप मिडिल स्कूल ले लीजिए। जब कोई मिडिल स्कूल की मांग करता था तो वे हाई स्कूल देने की बात करते थे। जहां हाई स्कूल की मांग होती थी वहां प्लस टू और प्लस टू की मांग होती थी तो कॉलेज और जहां कॉलेज की मांग होती थी तो वहां वे विश्वविद्यालय खोलने की बात करते थे। संस्थान खोलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन संस्थान खोलने के लिए पैसे, स्टाफ व भवन का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों की पढ़ाई आज डिस्टर्ब हो रही है उसकी जवाबदेही भी कांग्रेस पार्टी की है। स्कूल खोल दिए, अध्यापक थे नहीं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मात्र दो ही स्कूल बचे हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां

अध्यापक नहीं है लेकिन इन्होंने कई और रिक्त पदों का भरा है। माननीय सिंघा जी द्वारा जो डाटा इस सदन में प्रस्तुत किया गया मुझे लगता है कि वह कांग्रेस पार्टी के समय का था। जितनी संख्या गिनाई गई कि यहां डॉक्टर कम है या कोई दूसरे पदों की बात की गई तो यह सब इनकी पार्टी का डाटा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भरमौर और पांगी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भरमौर में मात्र तीन डॉक्टर थे।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

28-02-2020/1545/ए.एस.-एन.जी./1

श्री जिया लाल जारी.....

प्रदेश में जब माननीय श्री जय राम ठाकुर की सरकार आई और माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वास्थ्य मंत्री थे, अब मेरे विधान सभा क्षेत्र भरमौर में 11 डॉक्टर हैं और पांगी में 6 डॉक्टर हैं। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर नहीं थे उन सभी में आज डॉक्टर हैं। यदि कहीं पर डॉक्टरों की कमी रह गई होगी तो उसे भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। श्री जय राम ठाकुर और केन्द्र सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कॉलेज खुले हैं...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः कितने मैडिकल कॉलेज हैं? ...(व्यवधान)

श्री जिया लालः सभी हैं, दो आपके चार हमारे...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप मुझे सम्बोधित करें, श्री मुकेश जी की बातों का जवाब न दें।

श्री जिया लालः अध्यक्ष महोदय, उन सभी मैडिकल कॉलेजों में डाक्टरों की नई खेप तैयार करके बहुत जल्द डॉक्टरों की कमी को पूर्ण कर लिया जाएगा।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने वाली थी तब एक ही स्थान पर 40-40 फट्टों को लगाकर शिलान्यास किया गया और कहा गया कि कार्य को बहुत शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन सभी योजनाओं के लिए न बजट का प्रावधान था, न यह मालूम था कि रास्तें कहां पर बनने हैं। मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि यदि फट्टे लगा कर सरकार

रिपीट होती तो आप आज विपक्ष में न होते और हमारे द्वारा जो फट्टे लगाए जा रहे हैं उनका उद्घाटन भी हमारे द्वारा ही किया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप भी 40-40 फट्टे लगा रहे हो क्या?...(व्यवधान)

श्री जिया लालः हम लगाएंगे तो उनका उद्घाटन भी हम ही करेंगे।...(व्यवधान) माननीय श्री जय राम ठाकुर जी बहुत ही दरिया-दिल वाले मुख्य मंत्री हैं।

28-02-2020/1545/ए.एस.-एन.जी./2

कांग्रेस पार्टी के जो लोग उनका विरोध करते हैं वे सभी यहां पर तो उनका विरोध करते हैं लेकिन उनके पास जाकर अपना काम करवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री जय राम ठाकुर जी को जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया मुख्य मंत्री हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इनका काम मत किया करो, ये हमारे कभी नहीं हो सकते ---(***)---व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया इस लाइन को expunge करवा दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जिया लाल जी ने सांप कहते हुए किसी का भी ज़िक्र नहीं किया है लेकिन फिर भी इन शब्दों को expunge कर दिया जाए।

श्री जिया लालः अध्यक्ष महोदय, पिछले कल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस माननीय सदन में कह रहे थे कि पुरानी बोतल में नई शराब डाली जा रही है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बोतल भी नई है, शराब भी नई है, मुख्य मंत्री भी नए हैं और सरकार भी नई है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 5 साल तक इतना काम करेगी कि विपक्ष के सदस्यों की संख्या और कम हो जाएगी।...(व्यवधान) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण इस माननीय सदन में रखा गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28-02-2020/1545/ए.एस.-एन.जी./3

अध्यक्षः धन्यवाद श्री जिया लाल जी, बहुत ही थोड़े समय में आपने सारा विषय यहां पर रखा है। वैसे तो सत्र का समय सायं 5.00 बजे तक होता है लेकिन पक्ष और विपक्ष की सामुहिक राय हो तो सत्र को 4.00 बजे तक चला सकते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्या श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी को बोलने का समय दिया जाएगा?

अध्यक्षः हां, इन्हें बोलने का समय दिया जाएगा और ये 15 मिनट में अपना विषय रखते हुए चर्चा में भाग लेंगे और उसके बाद आज की बैठक का समापन होगा। अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू)ः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय जी द्वारा दिनांक 25-02-2020 को दिए गए अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझ से पूर्व पक्ष और विपक्ष के वक्ताओं ने काफी लम्बी-चौड़ी बातें कही हैं।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2020/1550/JK/DC/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः-------**जारी**-------

खासकर अपोजिशन साइड से भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने काफी लम्बी-चौड़ी बात की है। चाहे हमारे ठाकुर राम लाल जी हैं या दूसरे माननीय सदस्यगण हैं लेकिन मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं ज्यादा बात भी यहां पर नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ इतना जरूर बताना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया, जैसे मेरे से पूर्व सदस्यों ने कहा कि यह सरकार का पिछले साल का लेखा-जोखा होता है।

सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां हैं, क्या काम किया है, सरकार द्वारा इसको तैयार किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस दस्तावेज को पढ़ रहा था, यह हिन्दी में 56 पृष्ठ और अंग्रेजी में 50 पेजिज़ का अभिभाषण है। राज्यपाल महोदय ने लगभग 2 घण्टे 5 मिनट तक इसको पढ़ा। मैंने भी इसको सुना और पढ़ा, मैंने पाया कि इसमें सरकार की कोई ऐसी उपलब्धियां साल या दो साल की नहीं है, जिनके लिए सरकार की तारीफ़ की जाए। यह बात ठीक है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में धारा 370 बात कही गई, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर इतना ज़रूर बताना चाहूंगा कि वह मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सब-ज्यूडिस है। दूसरी बात राम जन्म भूमि की आई और कोर्ट की जो लैंड में वर्डिक्ट आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि यह हमने किया है। अगर आपने किया तो ज्यूडिशरी को आप खत्म कर दो। अगर सब कुछ ही आपने करना है, ज्यूडिशरी भी आपने ही चलानी है और इसका श्रेय भी आप लोग ही लेना चाहते हैं तो आप ज्यूडिशरी को खत्म करो। यह तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। इसी तरह से मैं इस दस्तावेज में देख रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो इनके चुनावी वायदे थे, उनका ज़िक्र तो इस दस्तावेज में ही नहीं है और आज तक वे कोई भी वायदे पूरे नहीं हुए हैं। यहां जनमंच की बात भी दस्तावेज में आई। मैं उसके बारे में तो इतना ही बताना चाहूंगा कि जो यह जनमंच चलाया गया है, यह मिसयूज़ ऑफ फंडज़ है, अधिकारियों

28.02.2020/1550/JK/DC/2

और कर्मचारियों की प्रताड़ना है। पब्लिक के फंड का मिसयूज़ हो रहा है। इसका कोई भी फायदा नहीं है जैसे कि सरकार कहती है कि इसका हमने बहुत ज्यादा फायदा लिया है। इसी के साथ जो धर्मशाला में ग्लोबल इन्वैस्टर्ज़ मीट हुई थी, उसमें भी सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च किए लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं है। अगर आगे कुछ होगा तो अच्छी बात है। यदि आउटकम होगा या लाभ होगा तब उस वक्त बात आएगी तो हम आपका

धन्यवाद करेंगे। अभी तक तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ है जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करें।

अध्यक्ष महोदय, इस दस्तावेज में बेरोजगारी की कोई बात नहीं की गई है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नौजवान साथी हमारे बेरोजगार हो गए हैं। इसमें महंगाई का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पैट्रोल-डीज़ल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सिलैंडर की, सब्जियों की, दूध की कीमतें कहां पहुंच गई हैं लेकिन इस बारे में कोई भी ज़िक्र इस दस्तावेज में नहीं किया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि जो सरकार का दो साल दो महीने का कार्यकाल है, इसमें सरकार हर पहलू पर फेल हुई है। यहां पर राकेश सिंघा जी की भी बात आई। सिंघा साहब जब यहां पर अपना भाषण दे रहे थे तो इन्होंने वैकेंसीज़ की बात की। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत लम्बी-चौड़ी बातें हैं कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज़ हैं। यह दस्तावेज तो ठीक है लेकिन मैं एक कदम और आगे जा रहा हूं। आज की स्थिति यह है कि इससे भी ज्यादा वैकेसीज़ हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्ज़ की स्थिति बहुत खराब है। कई अस्पताल खाली पड़े हुए हैं,

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

28.02.2020/1555/SS-YK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागत :

हमारे माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी आज यहां नहीं है वे भी कुल्लू की बात कर रहे थे। पूरे प्रदेश की बात है कि आज डॉक्टर्ज़ नहीं हैं। मैं अपने रोहड़ू सिविल हॉस्पिटल की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस सिविल हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर्ज़ की सैंक्शंड स्ट्रैंथ है। आज उस हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि वहां पर 10 या 12 डॉक्टर्ज़ काम कर रहे हैं। उनको भी हमेशा डयूटी पर रहने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनको कभी कोर्ट में ऐविडैंस के लिए जाना पड़ता है और कभी छुट्टी भी लेनी पड़ती है।

यहां पर वन मंत्री महोदय नही हैं। मेरा रोहड़ू में ट्रांसपोर्ट का एक छोटा-सा डिपो है। जब मैं वहां एक दिन मीटिंग कर रहा था तो मैंने उनसे डाटा लिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी वैकेंसी पॉजिशन क्या है तो उन्होंने कहा कि आप सुन कर हैरान होंगे। उस डिपो में वैकेंसी पॉजिशन 100 से ऊपर निकली। वहां पर यह स्थिति है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कई विभागों में काफी वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह आज बिजली विभाग की बात आती है। बिजली के बारे में सिंघा साहब बात कर रहे थे। सिंघा साहब ने अपने ठियोग की बात की। इन्होंने शायद उसमें रामपुर, चौपाल और कुल्लू भी जोड़ा। मैं चाह रहा था कि अगर रोहड़ू भी बोलते तो शायद मुझे इस पर बोलने की आवश्यकता न होती। रोहड़ू में भी आज बिजली की बहुत खराब स्थिति है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी रोहड़ू से विलोंग करते हैं। इनको थोड़ा जगह के बारे में पता होगा। अगर इनके इलाके बम्नौली में फॉल्ट होगा तो लाइट लोअर कोटी में चली जाती है। अगर मेरे स्पैल में फॉल्ट पड़ेगा, जहां का मैं स्थाई निवासी हूं तो चुहारा साइड लाइट चली जाती है। अगर थोड़ी-सी हवा चल जाए तो लाइट की ऐसी स्थिति है, बुरे हाल हैं। ...(व्यवधान) आप भी कुछ करके दिखाओ। आपके सदस्य तो यहां बड़ा गुणगान करते हैं लेकिन आप (शिक्षा मंत्री से) भी कुछ करके दिखाओ। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं तो पूर्व मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी की बदौलत हूं। वैसे तो उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास किया। उन्होंने कभी किसी क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया। परन्तु जहां तक रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र का संबंध है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इनके समय में वहां पर बहुत काम हुए हैं। यह बात ठीक है कि पहले लकड़ी के पोल होते थे परन्तु अब लोहे के लगाने पड़ रहे हैं, यह स्थिति है।

28.02.2020/1555/SS-YK/2

एक और बात है। मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, यह आज का ही पेपर है, 'रोहड़ू में उपभोक्ताओं को 8 माह से नहीं मिले बिजली के बिल'। ये बिल कहां के हैं - पेखा, तांगनू, ड्यूदी। मैं इसकी बात सुनाना चाह रहा हूं, इसमें क्या लिखा है! अगर बिजली विभाग पास जाओ तो वे कहते हैं कि आप रीडिंग खुद लेकर आओ। अध्यक्ष महोदय, लोग रीडिंग भी लेकर जाते हैं फिर उनको दोबारा बोलते हैं कि यह रीडिंग ठीक नहीं है, आप इसे दोबारा लेकर आओ। ऐसे लोगों के चक्कर कटवाते रहते हैं। आज की डेट में यह स्थिति है।

इसी तरह से इस दस्तावेज में ज़िक्र हुआ कि दो साल में आपने कई बिल्डिंग्ज़ के उद्घाटन किये। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जितनी भी बिल्डिंग्ज़ और बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स के दो साल में उद्घाटन किये, उनके फाउंडेशन स्टोन आपने नहीं रखे। उनके फाउंडेशन स्टोन, पूर्व सरकार में राजा वीरभद्र सिंह के दौरान रखे गए हैं। आपकी सरकार के टाइम का ऐसा कोई प्रोजैक्ट नहीं है जिसकी फाउंडेशन स्टोन आपने रखी और उद्घाटन भी आपने किया होगा। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। आप दूर क्यों जाते हैं, हमारे यहां साथ ही स्टेट लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनी है, इसका फाउंडेशन स्टोन राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा था लेकिन उद्घाटन आपने किया। यह बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह से आपके सर्किट हाउस की बिल्डिंग शिमला में बनी, वह भी राजा वीरभद्र सिंह जी की बदौलत है। आज आपने उसका उद्घाटन जरूर किया। इसी तरह के0एन0एच0 में एक बिल्डिंग बनी है। इसी तरह शिक्षा मंत्री जी मैं रोहड़ू की बात करूंगा, जब आपकी सरकार बनी तो आप मंत्री बने और सबसे पहले आपने रोहड़ू का दौरा रखा। उस वक्त रोहड़ू में बरागटा जी बी0जे0पी0 के अध्यक्ष थे। वे कलारस के रहने वाले हैं। उनका एक रोड समाला से जूनीदार था। वह रोड 8-10 किलोमीटर का है। आपसे उन्होंने तीन किलोमीटर का उद्घाटन करवाया, सिर्फ उसी दिन वहां बस गई और उसके बाद वह रोड बंद है। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी का रोहड़ू दौरा गया था,

जारी श्रीमती के0एस0

28.02.2020/1600/केएस/एचके/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी---

मैंने तो माननीय मुख्य मंत्री जी को पिछले सत्र में भी कहा, जब वे रोहड़ू गए तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी, मैं भी वहां गया था, मैंने भी मुख्य मंत्री का स्वागत किया था। मैंने सोचा कि माननीय मुख्य मंत्री जी शायद इतनी भीड़ देखकर बहुत बड़ा तोहफ़ा दे कर जाएंगे। परन्तु उन्होंने जो वहां के लोकल लीडर बनते हैं, उन्होंने ठेकेदारों के किसी के दो लाख, किसी के तीन लाख तथा किसी के पांच लाख देने थे, वह घोषणा ज़रूर की और उद्घाटन जिन बिल्डिंगों के किए उनमें एक हमारे सीमा कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। शिक्षा मंत्री जी को पूरा पता है कि सीमा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक राजा

वीरभद्र सिंह जी की बदौलत बना था। उसका मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया। मुख्य मंत्री जी का नाम तो पट्टिका में लगना ही था और शिक्षा मंत्री के नाते आपका भी लगा दिया लेकिन साथ में वीरेन्द्र कश्यप जी का नाम भी लिख दिया जिनका कि उसके लिए कोई योगदान ही नहीं था। सांसद का तो उसमें कोई योगदान ही नहीं था। इसी तरह से समोही में एक पुल बना। उसका उद्घाटन भी इसी तरह किया। जिन सड़कों का पहले ही भूमि पूजन हुआ था, उनका भी आप भूमि पूजन कर गए। मेरे कहने का तात्पर्य है, ...घंटी...

अध्यक्षः माननीय सदस्य समय हो गया। आपने 4:00 बजे तक समाप्त करने के लिए कहा था।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, बस पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं वाइंड अप कर दूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलता।

अध्यक्षः बस अब काफ़ी हो गया। अब समाप्त करें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में मैं वाइंड अप कर दूंगा।। will wind-up within two or three minutes and not take more time. जैसा कि विक्रमादित्य सिंह जी भी कल कह रहे थे, ठीक बात है, अपोजीशन का मतलब यह नहीं है कि हर चीज़ को अपोज़ ही करना है और मैं भी यही मानता हूं। मेरी यह व्यक्तिगत सोच है। अगर आप अच्छा

28.02.2020/1600/केएस/एचके/2

काम करेंगे तो मैं उसका यहां भी स्वागत करुंगा, आपका धन्यवाद करुंगा और अगर अपने चुनाव क्षेत्र में बोलना होगा तो वहां भी करुंगा परन्तु सरकार बने हुए अभी तक दो साल का समय हो चुका है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका मैं धन्यवाद करुं।

अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं है लेकिन जैसे कि विक्रमादित्य सिंह जी ने कल कहा था कि जो हमारी प्लानिंग की मीटिंग होती है, वैसे तो मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी यह बात की है, परन्तु मैं आज भी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाने की

बात कहूंगा कि हमारे अधिकतर विधायकों की नाबार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। अगर वह लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी तो जो विधायक प्रायोरिटी देते हैं या जो प्लानिंग की मीटिंग होती है, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए जो अभी बजट पेश किया जाना है, उसमें उस लिमिट को बढ़ाने की कृपा करें। उसका लाभ सिर्फ मुझे ही नहीं होगा, अधिकतर ऐसे विधायक हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं, हमारी लिमिट खत्म हो चुकी है तो प्रायोरिटी तो हमारी वैसे भी यूज़लैस हो जाएगी।

इसी तरह यहां पर 69 एन.एच. की बात आई थी, वह आज कहां गया? वह तो पेपर से कहीं गायब ही हो गया है। ऐसी-ऐसी कई योजनाएं हैं। आपने एक बात कर दी। एक तो आपकी सरकार जो ड्रग्ज़ मेनेस जो युवाओं के लिए सोसायटी के लिए थ्रैट है, उसमें भी आपकी सरकार की काफी हद तक नाकामी रही है। आज आप हर तीसरे दिन अख़बार में पढ़ते हैं कि फ्लां जगह ड्रग्ज़ पकड़ी गई लेकिन आपने तो शराब सस्ती कर दी और साथ में आदेश कर दिए कि रात के दो-ढाई बजे तक आप शराब पीते रहो।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं क्योंकि यह आपके विभाग की भी बात है। आज क्या हो रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूलों के सरकारी कार्यक्रमों में हारे-नकारे लोग चीफ़ गैस्ट बन कर जा रहे हैं। उनके पास कोई ओहदा होता तब तो हम मान सकते थे लेकिन वे आज चीफ गैस्ट के रूप में जा

28.02.2020/1600/केएस/एचके/3

रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं जो कि सोचने की बात है। अगर आप यह बोलेंगे कि आपके समय में भी ऐसा होता था तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे समय में भी ऐसा होता था तो आप वहां क्यों बैठे हैं, यहीं बैठे रहते, हम ही उस तरफ से सरकार चलाते।

अध्यक्ष महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपके ही डिपार्टमैंट की बात है, वर्ष 2015 में पब्बर नदी का चैनेलाइजेशन हुआ। केन्द्र को 190 करोड़ रुपये के आस-पास स्कीम गई। सेंक्शन हो गई उसका फाउंडेशन स्टोन भी हो गया था,

28.2.2020/1605/av/yk/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा------जारी

और काम भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई उसने इसका पैसा बंद कर दिया। इस बारे में शायद पिछले कल सवाल लगा था मगर शायद उसकी बारी नहीं आई थी। आपने उसमें भी गोल-मोल जवाब दिया है। पिछली बार आपकी तरफ से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि मेरा नाम लिया है; मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आपकी तरफ से एक माननीय सदस्य बोलना चाह रहे थे कि वह स्कीम तो पास होकर आ गई है और यह पिछले सत्र की बात है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने कहा था कि मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। वैसे आपकी सारी बातें आ गई हैं।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। अभी यहां पर कृषि मंत्री जी नहीं बैठे हैं। आपकी सरकार आई और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो काम हुए। उसमें माननीय जल शक्ति मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी; क्योंकि शिक्षा मंत्री जी रोहड़ू से वाकिफ़ हैं। वहां के लिए लोक निर्माण विभाग का लगभग 1.20 करोड़ रुपये की राशि का रैस्ट हाउस सैंक्शन हुआ था। उस बारे में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने अनाउंसमैंट की थी। उसके लिए पैसा सैंक्शन हो गया था और फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया था। मगर जैसे ही आपकी पार्टी की सरकार सत्ता में आई आपने वह काम बंद कर दिया। इसके अलावा रोहड़ू में सब्जी मंडी बन रही थी मगर उसका काम भी बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क का कार्य चला हुआ था, जिसको आपकी सरकार ने बंद कर दिया। ...(घंटी)अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो 25 जनवरी, 2020 को अपना अभिभाषण पढ़ा है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

अध्यक्ष : माननीय जल शक्ति मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ब्राक्टा जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और विशेषकर पब्बर नदी के चेनेलाइजेशन के बारे में कहा है। वर्ष 2015-16 में इसकी टी0ए0सी0 हो गई थी। हमने आपको काम करने से कब रोका? उस समय तो आपकी सरकार थी। वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में आपकी सरकार थी और हमने आपको काम करने से नहीं रोका। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर भारत सरकार से टी0ए0सी0 हो जाए तो वहां से इंवैस्टमैंट आनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार से जब तक इंवैस्टमैंट क्लीयरेंस न हो तब तक वहां से पैसा नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश की चार योजनाएं हैं जिसमें से एक कांगड़ा, एक रोहडू (शिमला), एक हमीरपुर और एक मण्डी की है। उन चारों योजनाओं की अब टी0ए0सी0 हो चुकी है, आपकी पहले हो गई थी और हमने चारों की इंवैस्टमैंट क्लीयरेंस करवा दी है जो कि अब फंडिंग के लिए लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि 1 अप्रैल, 2020 के उपरान्त हमारा जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि इनके लिए धन का आवंटन हो जाए ताकि हम इन चारों योजनाओं का काम शुरू कर सकें।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद और विशेषकर के जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया।

अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार, 2 मार्च, 2020 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 28 फरवरी, 2020 **सचिव**